09
अगस्त, 2026
रविवार

नई दिल्ली
मूल्य : 01 रुपए
पृष्ठ : 08
वर्ष : 14
अंक : 129

RNI No. DELMUL/2012/47011

अनोखे अंदाज़ और निराले तेवर के साथ इन्साफ की डगर पर

टाइम्स ऑफ़ पीडिया

www.timesofpedia.com
Email : timesofpedia@gmail.com

धोनी का कमरा सभी के लिए खुला रहता था : रहाणे 07

संक्षिप्त वार्ता

ई-20 यानी दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ई-20 पेट्रोल को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर करीब 53 सेकेंड का एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वह एक कार की पेट्रोल टंकी का ढक्कन खोलकर ई-20 ईंधन को लेकर सवाल उठाते नजर आए। वीडियो में राहुल ने कार की पेट्रोल टंकी का ढक्कन खोलकर उसके अंदर झांका और कहा, ह्यनॉर्मलीह्ण हम कहते हैं कि दाल में काला है, लेकिन यहां पूरी दाल ही काली है।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश में इस समय भ्रष्टाचार के कई मामले हैं और ई-20 ईंधन भी उनमें से एक है। उन्होंने कहा कि ई-20 के कारण लोगों की कार और स्कूटर खराब हो रहे हैं। उनका दावा है कि इसका असर केवल लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर ही नहीं पड़ रहा, बल्कि वाहन खराब होने के कारण लोगों की जेब पर भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। राहुल गांधी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

अभिनेता सलमान के घर पर तैनात सिपाही की मौत

मुंबई। अभिनेता सलमान खान के बांद्रा स्थित आवास ह्यगैलेक्सी अपार्टमेंटह्ण के बाहर सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी की अचानक मौत हो गई। मृतक की पहचान 41 वर्षीय कांस्टेबल गणेश के रूप में हुई है। वह पिछले कई वर्षों से सलमान खान की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात थे और घटना के वक्त घर के बाहर ड्यूटी कर रहे थे। शुक्रवार को ड्यूटी के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़े। मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों और सुरक्षा कर्मचारियों ने तुरंत उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। हालांकि, डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, कांस्टेबल गणेश की मौत हार्ट अटैक से होने की आशंका है। हालांकि, मौत के वास्तविक कारण की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगी।

अमित शाह एफसीआ-रए और विपक्ष हंगामें की तैयारी में जुटा

नई दिल्ली। संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी हफ्ते में एफसीआरए संशोधन विधेयक को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ने के आसार हैं। कांग्रेस ने शुक्रवार को तीन लाइन का व्हिप जारी कर अपने सभी लोकसभा सांसदों को 10, 11 और 12 अगस्त को सदन में अनिवार्य रूप से मौजूद रहने का निर्देश दिया है। विपक्षी गठबंधन के अन्य दल भी अपने सांसदों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की तैयारी में हैं। माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह एफसीआरए बिल पेश करने की तैयारी कर रहे है तो विपक्ष हंगामे के लिए कमर कस रहा है।

एफसीआरए संशोधन विधेयक 10 या 12 अगस्त को लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना है। गृह मंत्रालय से जुड़े इस विधेयक पर विपक्ष की नजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी पर भी है। विपक्ष मॉनसून सत्र की शुरूआत से ही 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री से सदन में बयान देने की मांग कर रहा है। इस मुद्दे पर सदन में कई बार गतिरोध हो चुका है। कांग्रेस ने अपने सहयोगी दलों से भी अगले सप्ताह सदन में पूरी ताकत के साथ मौजूद रहने को कहा है।

सिर्फ सवाल मत पूछिए, समाधान भी खोजिए

वेब वार्ता, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में छात्रों से बदलती दुनिया के साथ लगातार सीखते रहने और समस्याओं के समाधान खोजने का आह्वान किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि छात्र यहां से केवल डिग्री लेकर नहीं, बल्कि सपने और जिम्मेदारियां लेकर निकल रहे हैं। अगले 20-30 साल में वे जो काम करेंगे, वही विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव तैयार करेगा।

आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में 3,000 से अधिक छात्र शामिल हुए, जिनमें 587 पीएचडी शोधार्थी भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को डिग्रियां प्रदान करने के साथ मेडल भी पहनाए। उन्होंने कहा कि आईआईटी से निकलकर छात्रों के जीवन की एक नई यात्रा शुरू हो रही है।

परिवारों को अपने बच्चों पर गर्व है और देश को भी उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। यहां पीएम मोदी ने छात्रों से कहा कि हॉस्टल, दोस्तों, प्रतियोगिताओं, मेस के खाने और संस्थान से जुड़ी तमाम यादें जीवनभर उनके साथ रहेंगी। शिक्षक, प्रोफेसर और सपोर्ट स्टाफ भी समय के साथ परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे अपनी सफलता में आईआईटी से जुड़े लोगों और रिश्तों को हमेशा याद रखें।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया, तकनीक और इंडस्ट्री तेजी से बदल रही हैं। ऐसे समय में किसी को यह पता नहीं है कि अगले 20 या 30 साल की दुनिया कैसी होगी। इसलिए वही लोग आगे बढ़ेंगे, जो लगातार सीखते रहेंगे और नई चुनौतियों के समाधान तलाशेंगे। उन्होंने छात्रों से केवल सवाल उठाने के बजाय उनके समाधान खोजने की मानसिकता विकसित करने को कहा।

देश में 37 सुपरकंप्यूटर सक्रिय

राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन के तहत देश में अब तक 37 सुपरकंप्यूटर स्थापित किए जा चुके हैं और ये सभी सक्रिय हैं। इन्हें आईआईटी, आईआईएससी, एनआईटी, सी-डीएसी, आईसर समेत प्रमुख शोध संस्थानों में लगाया गया है। परम सिद्धि, परम प्रवेग, परम शक्ति, परम संगणक, परम सेवा, परम रुद्र, परम ब्रह्मा, परम युक्ति और परम शिवाय इनमें प्रमुख हैं।

परम प्रज्ञा सुपरकंप्यूटर का उद्घाटन

प्रधानमंत्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित एआई आधारित हाई-परफॉर्मेंस सुपरकंप्यूटर परम प्रज्ञा का रिमोट माध्यम से उद्घाटन किया। यह सुपरकंप्यूटर जटिल गणनाओं को तेज गति से करने के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, एडवांस्ड कंप्यूटिंग और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

भारत के 22 उपग्रहों में से 20 पर अंतरिक्ष मलबे से टकराने का खतरा

अंतरिक्ष एजेंसी इसरो टक्कर रोकने के लिए कई बाद बदल चुकी हैं कक्षाएं

वेब वार्ता, नई दिल्ली

अंतरिक्ष में बढ़ता मलबा भारत के उपग्रहों के लिए चुनौती बनता जा रहा है। सरकार के मुताबिक पृथ्वी की निचली कक्षा में संचालित भारत के 22 उपग्रहों में से 20 पर अंतरिक्ष मलबे से टकराने का खतरा मंडरा रहा है। आधुनिक दौर में संचार, इंटरनेट, मौसम पूर्वानुमान, नेविगेशन, आपदा प्रबंधन और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसी अनेक अहम सेवाएं उपग्रहों पर निर्भर हैं। ऐसे में अंतरिक्ष में बढ़ते मलबे की समस्या केवल अंतरिक्ष अभियानों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर आम लोगों के दैनिक जीवन पर भी पड़ सकता है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में कहा कि पृथ्वी से दो हजार किलोमीटर तक की ऊंचाई वाली लो अर्थ ऑर्बिट में अंतरिक्ष मलबे और अन्य अंतरिक्ष वस्तुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। इस कारण इस क्षेत्र में संचालित उपग्रहों के टकराने की आशंका भी ज्यादा रहती है। उन्होंने बताया कि 2026 में अब तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने संभावित टक्करों से बचाने के लिए नौ बार उपग्रहों की कक्षाओं में बदलाव किया है। 2025 में ऐसे 20 बदलाव किए गए थे। इस प्रक्रिया को ह्यकोलिजन अवॉइडेंस मैन्यूवरह्ण कहा जाता है, जिसके तहत किसी संभावित टक्कर से पहले उपग्रह की कक्षा में जरुरी परिवर्तन कर उसे सुरक्षित किया जाता है।

सरकार ने साफ किया कि भारत अंतरिक्ष मलबे के प्रबंधन से जुड़े अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में सक्रिय भागीदारी निभा रहा है। 2024 में भारत ने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन की घोषणा की थी। इस पहल का उद्देश्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के अंतरिक्ष अभियानों में नए मलबे के निर्माण को न्यूनतम करना और भविष्य में शून्य मलबा लक्ष्य की दिशा में काम करना है। इसरो भी इसी दिशा में कई तकनीकों और रणनीतियों पर कार्य कर रहा है।

विशेषज्ञों के मुताबिक अंतरिक्ष मलबे में निष्क्रिय उपग्रह, रॉकेटों के छोड़े गए हिस्से, टूटे उपकरण और टक्करों से बने लाखों छोटे-छोटे कण शामिल हैं। ये अत्यधिक गति से अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं और इनका छोटा सा टुकड़ा भी किसी सक्रिय उपग्रह को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। इससे संचार सेवाएं, इंटरनेट, जीपीएस, मौसम पूर्वानुमान और अंतरिक्ष मिशन प्रभावित हो सकते हैं।

चांद से टकराया स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट, आइंस्टीन क्रेटर पर हुआ गड्ढा

वेब वार्ता, वाशिंगटन। स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट चांद की सतह से टकराकर नष्ट हो गया। करीब 8,690 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हुई इस टक्कर के बाद चंद्रमा के आइंस्टीन क्रेटर के पास एक नया गड्ढा बन गया है। इस पूरी घटना को दक्षिण कोरिया के चंद्र ऑर्बिटर दानूरी ने अपने कैमरे में कैद किया है। ऑर्बिटर ने टक्कर से पहले और बाद की तस्वीरें भेजी हैं, जिनमें चंद्रमा की सतह पर हुए बदलाव और मलबे के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस घटना से चंद्रमा की सतह और उसकी संरचना को समझने में अहम मदद मिलेगी। फाल्कन 9 रॉकेट को जनवरी 2025 में दो निजी चंद्र लैंडरों को अंतरिक्ष में भेजने के मिशन के तहत प्रक्षेपित किया गया था। इनमें ब्लू घोस्ट और रेजिलिएंस लैंडर शामिल थे। ब्लू घोस्ट सफलतापूर्वक मार्च 2025 में चंद्रमा पर उतर गया, जबकि रेजिलिएंस लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मिशन पूरा होने के बाद रॉकेट का पहला चरण पृथ्वी पर लौट आया, लेकिन दूसरा चरण अंतरिक्ष में ही रह गया। करीब चार हजार किलोग्राम वजनी यह हिस्सा ईंधन खत्म होने के बाद लंबे समय तक अंतरिक्ष में भटकता रहा और अंततः गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से चंद्रमा से टकरा गया।

संसद के मकर द्वार पर पोर्च निर्माण के निर्देश, लोकसभा स्पीकर बिरला ने की बैठक

नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों और कर्मचारियों को बारिश से होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने अधिकारियों को नए संसद भवन के मकर द्वार पर एक पोर्च के निर्माण की संभावना तलाशने और इसका प्रस्ताव तैयार करने को कहा हैं। यह पहल मॉनसून सत्र के दौरान दिल्ली में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के मद्देनजर की गई है।

स्पीकर बिरला ने इस संबंध में सीपीडब्ल्यूडी, आर्किटेक्ट्स और संबंधित एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उनका मानना है कि संसद भवन के महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार पर पोर्च का निर्माण सांसदों और

अन्य कर्मचारियों के लिए बेहद फायदेमंद होगा, जिससे उन्हें बारिश के दौरान परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अधिकारियों ने बताया कि यह निर्देश मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दिए गए हैं।

पुराने संसद भवन में कई प्रवेश द्वारों पर पहले से ही पोर्च की सुविधा मौजूद थी, जिसमें सांसदों द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य प्रवेश द्वार भी शामिल था। इसी तर्ज पर, लोकसभा अध्यक्ष ने आर्किटेक्ट और सीपीडब्ल्यूडी से नए संसद भवन के मकर द्वार पर भी ऐसी ही सुविधा बनाने के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट मांगी है।

एक अलग घटनाक्रम में, केंद्रीयगृ ह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। यह मुलाकात तब हुई जब प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी जैसे मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ है। विपक्ष 20 जुलाई को छात्रों पर पुलिस द्वारा बल प्रयोग करने के मामले में शाह से जवाब की मांग कर लोकसभा की कार्यवाही में लगातार व्यवधान डाल रहा है।

गुजरात यूनिवर्सिटी में बड़ा प्रशासनिक फैसला

पूर्व वीसी के कार्यकाल में नियुक्त 10 अधिकारी निलंबित

अहमदाबाद। गुजरात यूनिवर्सिटी ने पूर्व कुलपति नीरजा गुप्ता के कार्यकाल में की गई नियुक्तियों को लेकर बड़ा कदम उठाकर 10 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। इन अधिकारियों की नियुक्ति और वेतन संरचना को लेकर लंबे समय से विवाद था। आरोप है कि इन्हें अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था और कई अधिकारियों को हर महीने लाखों रुपये वेतन मिल रहा था, जिसमें कुछ की मासिक सैलरी 5 लाख रुपये तक पहुंच

रही थी।

गुजरात यूनिवर्सिटी में इन नियुक्तियों के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही थी। इसके बाद कार्यवाहक कुलपति जगदीश जोशी ने 5 अगस्त को तीन सदस्यीय जांच समिति गठित कर नियुक्तियों की प्रक्रिया, योग्यता और नियमों की समीक्षा के आदेश दिए थे। समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई की गई। निलंबित अधिकारियों में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हैं। कार्यवाहक कुलपति के अनुसार, जांच रिपोर्ट में उठाए गए सवालों के आधार पर सभी अधिकारियों को अगले आदेश तक निलंबित किया है। इन नियुक्तियों को लेकर लंबे समय से पारदर्शिता और नियमों के पालन पर सवाल उठ रहे थे।

114 में से 94 राफेल विमानों का उत्पादन भारत में होगा

वेब वार्ता, नई दिल्ली

भारत की वायुसेना को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ा है। फ्रांस ने 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए भारत को विस्तृत तकनीकी और व्यावसायिक प्रस्ताव सौंप दिया है। करीब 3.25 लाख करोड़ रुपये के इस रक्षा सौदे में बड़ी संख्या में विमानों का निर्माण भारत में करने का प्रस्ताव रखा गया है। प्रस्ताव के अनुसार, कुल 114 राफेल विमानों में से 94 का उत्पादन भारत में किया जाएगा, जबकि 20 विमान पूरी तरह तैयार स्थिति में भारत को मिल सकते हैं। इस सौदे का उद्देश्य भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ाना और पुराने लड़ाकू विमानों की कमी को पूरा करना है।

फ्रांस की विमान निमार्ता कंपनी डसॉल्ट एविएशन के साथ मिसाइल निमार्ता एमबीडीए, इंजन निमार्ता सफ्रान और रक्षा तकनीक कंपनी थेल्स जैसी संस्थाएं भारतीय औद्योगिक साझेदारों के साथ मिलकर उत्पादन में भूमिका निभा सकती हैं। इससे भारत में रक्षा निर्माण और तकनीकी क्षमता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

भारत इस प्रस्ताव का मूल्यांकन खासतौर पर स्वदेशीकरण के नजरिए से कर रहा है। सरकार की कोशिश है कि राफेल विमानों में अधिक से अधिक भारतीय तकनीक और

हथियारों का इस्तेमाल किया जाए। इसमें स्वदेशी अस्त्र एयर-टू-एयर मिसाइल और अन्य भारतीय प्रणालियों के एकीकरण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इस परियोजना से भारतीय रक्षा उद्योग को बड़ा फायदा मिलने की संभावना है। अनुमान है कि इससे करीब 1.6 लाख करोड़ रुपये के कारोबारी अवसर पैदा हो सकते हैं। टाटा समूह, लार्सन एंड टुब्रो समेत कई भारतीय कंपनियां उत्पादन प्रक्रिया में शामिल हो सकती हैं। इससे रक्षा क्षेत्र में रोजगार और तकनीकी विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

महत्वपूर्ण मानी जा रही है

भारतीय वायुसेना लंबे समय से घटते लड़ाकू स्क्वाड्रन और पुराने विमानों की समस्या से जूझ रही है। मिग लड़ाकू विमानों की चरणबद्ध विदाई और स्वदेशी लड़ाकू विमान परियोजनाओं में देरी के बीच राफेल सौदा बेहद अहम माना जा रहा है। फिलहाल भारतीय वायुसेना और नौसेना के पास राफेल विमानों के लिए कुल 62 विमानों का ऑर्डर है। अगर 114 नए विमानों की खरीद पूरी होती है तो भारत के पास राफेल लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़कर 176 हो जाएगी। इसके अलावा नौसेना भी समुद्री सुरक्षा जरूरतों के लिए अतिरिक्त राफेल विमानों की खरीद पर विचार कर रही है। रक्षा मंत्रालय अब फ्रांस के प्रस्ताव की तकनीकी और वित्तीय समीक्षा करेगा। इसके बाद सौदे की अगली प्रक्रिया तय होगी। चीन और पाकिस्तान की सैन्य क्षमताओं को देखते हुए यह डील भारत की हवाई सुरक्षा और रणनीतिक क्षमता के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

राम मंदिर में 3300 करोड़ का हिसाब-किताब सही, सरकारी सूत्रों ने खारिज किया घोटाले का दावा

वेब वार्ता, लखनऊ

अयोध्या का राम मंदिर, जो हाल ही में दान चोरी को लेकर सुर्खियों में था, अब सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बड़े वित्तीय घोटाले के आरोपों से मुक्त हुआ है। सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि मंदिर के लिए जमा हुए करीब 3300 करोड़ रुपये के दान का पूरा हिसाब-किताब सही है, और इसमें किसी बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ी का कोई सबूत नहीं मिला है। समस्या केवल दान की नकदी गिनने के दौरान हुई एक अलग चोरी की घटना से संबंधित है।

सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय लेनदेन पूरी तरह पारदर्शी हैं और इसका ऑडिट स्वतंत्र बाहरी ऑडिटर एम/एस वी शंकर अय्यर एंड कंपनी द्वारा किया गया है। ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण पर करीब 1,800 करोड़ और जमीन खरीद पर 400 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। बताया गया कि सभी भुगतान बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से किए गए हैं, और बड़े लेनदेन में किसी भी तरह का नकद लेन-देन नहीं हुआ है, जिससे व्यापक वित्तीय अनियमितता के आरोपों का कोई

ठोस आधार नहीं बचता।

दान की राशि से जुड़ी हेराफेरी दरअसल एक विशिष्ट चोरी का मामला है। सूत्रों ने बताया कि दान पेटी (हुंडी) से निकली नकदी को मशीन से गिनने से पहले हाथों से अलग करते समय, एसबीआई द्वारा नियुक्त एजेंसी सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज (एसएसएस) के छह बाहरी कर्मचारियों ने चोरी को अंजाम दिया। इन सभी आरोपियों की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई और उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तार किए गए कर्मचारियों में से कोई भी राम मंदिर ट्रस्ट या मंदिर प्रशासन का हिस्सा नहीं था।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, घटना के बावजूद श्रद्धालुओं का भरोसा कम नहीं हुआ है, राम मंदिर को मिलने वाले दान में कोई कमी नहीं आई है और वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में हर महीने औसतन करीब 5 करोड़ रुपये का दान हुंडी के जरिए प्राप्त होता रहा। योगी सरकार ने इस घटना को केवल एक अलग चोरी का मामला बताया है, जिसे पूरे राम मंदिर ट्रस्ट की वित्तीय व्यवस्था से जोड़कर देखना अनुचित है।

...सुप्रीम कोर्ट की निगरानी है

केंद्र सरकार ने जमीन खरीद में अनियमितता के आरोपों को सिरे से खारिज किया है, यह बताकर कि पूरी जमीन का भुगतान बैंक-से-बैंक ट्रांसफर के माध्यम से हुआ है। जमीन की कीमतें बढ़ने का कारण सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलाके में संपत्ति मूल्यों में वृद्धि और व्यावसायिक ढांचों के लिए दिए गए मुआवजे को बताया गया है। मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच टीम (एसआईटी) पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी है, जो प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित कर रही है।

संपादकीय

भुगतान पर अड़ंगा: यूपीआई लेन-देन पर सेवा शुल्क

यूपीआई लेन-देन पर बैंकों और भुगतान प्रोसेस करनेवालों को शुल्क लगाने की इजाजत देने का सरकार का फैसला हालांकि अभी लंबित है, लेकिन इसने कई नीतिगत सवाल खड़े कर दिये हैं। किसी आधिकारिक निर्णय की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इसकी तैयारियां नजर आ रही हैं। जो इकलौता आधिकारिक बदलाव किया गया है वह है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स ऐक्ट में संशोधन, जिससे अब सरकार को यह अधिसूचित करने की इजाजत मिलेगी कि किस-किस तरह के लेन-देन पर शुल्क लग सकता है।

यह कराधान और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 के जरिए किया गया, जिसे हाल ही में लोकसभा में बिना किसी बहस के पारित किया गया। इस कानून से पहले, यूपीआई और रूपे डेबिट कार्ड लेन-देन साफ तौर पर किसी भी तरह के शुल्क से मुक्त थे। सरकारी सूत्रों का कहना है कि इस शुल्क की इजाजत एक-डेढ़ करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर वाले बड़े व्यापारियों द्वारा हुए लेन-देन और 2,000 रुपये से अधिक मूल्य के लेन-देन के लिए ही दी जा सकती है। इससे सभी यूपीआई लेन-देनों में से लगभग 5 फीसदी पर ही शुल्क लगेगा। हालांकि, संशोधित कानून सरकार को यह गुंजाइश बढ़ाने की शक्ति प्रदान करता है। यह भी डर है कि व्यापारी इस लागत का बोझ डालेंगे उपभोक्ताओं पर, जो नकदी की ओर लौटना पसंद करेंगे क्योंकि उसका इस्तेमाल निःशुल्क है। खैर, इस मुद्दे को भुगतान इकोसिस्टम के लिहाज से भी देखा जाना चाहिए। यूपीआई को साल 2020 में निःशुल्क किया गया। भुगतान कंपनियों का कहना है कि वे तब से यूपीआई को बनाये रखने और चलाने का खर्च उठा रही हैं। जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने हाल में कहा, यूपीआई के लिए किसी व्यक्ति को तो भुगतान करना पड़ेगा। शायद उनका मतलब था कि अब वह किसी व्यक्ति भुगतान प्रोसेस करनेवाले या बैंक नहीं होने चाहिए।

हालांकि, लागत का बोझ अकेले इन भुगतान कंपनियों ने नहीं उठाया है। करदाता पहले ही इसका कुछ हिस्सा वहन कर रहे हैं। साल 2021 में, सरकार एक योजना लेकर आयी जिसके तहत उसने छोटे व्यापारियों द्वारा 2,000 रुपये तक के लेन-देनों की प्रोसेसिंग लागत की आंशिक भरपाई के लिए, भुगतान प्रोसेस करनेवालों और बैंकों को सब्सिडी का भुगतान किया। सरकार इसके लिए पहले ही 11,349 करोड़ रुपये भुगतान कर चुकी है, तथा साल 2026-27 के लिए और 2,000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है। सवाल है कि क्या ग्राहकों और व्यापारियों को अतिरिक्त शुल्क चुकाने के लिए कहा जाना चाहिए, जबकि उनके करों में से कुछ का इस्तेमाल पहले ही इस काम के लिए किया जा रहा है। इस धारणा को लेकर भी कुछ गुस्सा है कि सरकार ने नोटबंदी के जरिए लोगों को यूपीआई इस्तेमाल करने की ओर इसीलिए धकेला ताकि अब उस पर शुल्क वसूलने की इजाजत दे सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि ऐसे शुल्क से भुगतान कंपनियों को बुनियादी ढांचे, नवाचार और सुरक्षा में ज्यादा निवेश करने में मदद मिलेगी। यूपीआई के विकास के लिए भुगतान की खातिर आरबीआई के पास संसाधन हैं। इसका इस्तेमाल करने से उस भारी अधिशेष में बस थोड़ी-सी कमी आयेगी जो वह हर साल केंद्र को हस्तांतरित करता है, लेकिन इससे सरकार एक ऐसे निर्णय से बच जायेगी जिसकी अलोकप्रियता लगातार बढ़ रही है।

पुलिस को भी है प्रतिकार का अधिकार

हाल में दिल्ली के जंतर-मंतर पर काकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नेतृत्व में हुए आंदोलन के दौरान पुलिस द्वारा कथित रूप से पैलेट गन के प्रयोग को लेकर पूरे देश में व्यापक बहस छिड़ गई है। घटना की जांच भी प्रारंभ हो चुकी है।

सवाल यह है कि पैलेट गन का प्रयोग हुआ या नहीं? यदि हुआ तो किन परिस्थितियों में हुआ? किंतु इस पूरे विवाद के बीच एक महत्वपूर्ण पक्ष लगभग चर्चा से बाहर है कि ऐसी परिस्थितियों में पुलिस को कानून क्या अधिकार देता है? मैंने अनेक बार ऐसे हालात देखे हैं, जब कुछ ही मिनटों में शांतिपूर्ण प्रतीत होने वाला प्रदर्शन हिंसक रूप धारण कर लेता है। ऐसे समय में पुलिस के प्रत्येक निर्णय का सीधा संबंध लोगों के जीवन, सार्वजनिक संपत्ति और कानून-व्यवस्था से होता है। इसलिए किसी भी घटना का मूल्यांकन केवल भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि कानून और वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए।

प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण ढंग से विरोध दर्ज कराने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, लेकिन यह अधिकार असीमित नहीं है। जब कोई प्रदर्शन हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, पथराव अथवा सार्वजनिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बन जाता है, तब राज्य का संवैधानिक दायित्व है कि वह कानून-व्यवस्था बहाल करे। पूर्व में भारतीय दंड संहिता यानी आइपीसी की धारा 141 में गैर-कानूनी जमावड़े की परिभाषा दी गई थी।

अब यह प्रविधान भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 189 में निहित है। यदि पांच या उससे अधिक व्यक्ति किसी ऐसे उद्देश्य से एकत्र हों, जो कानून के विरुद्ध हो, तो वह गैर-कानूनी जमावड़ा माना जाएगा। इसमें सरकार के वैधानिक कार्यों में बाधा डालना, अपराध करना, सार्वजनिक अथवा निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, बलपूर्वक किसी की संपत्ति पर कब्जा करना अथवा किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करने के लिए विवश करना शामिल हो सकता है। भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 189, 190 और 191 ऐसे गैर-कानूनी जमावड़े तथा दंगों में शामिल व्यक्तियों के लिए दंड का प्रविधान करती हैं। केवल हिंसा करने वाला व्यक्ति ही नहीं, बल्कि जानबूझकर ऐसे हिंसक जमावड़े का हिस्सा बने लोग भी कानूनी दायरे में आते हैं।

अब प्रश्न यह है कि ऐसी स्थिति में पुलिस क्या करे? इसका उत्तर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धाराओं 148 से 151 में मिलता है, जिन्होंने पूर्ववर्ती दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धाराओं 129 से 131 का स्थान लिया है। व्यवस्था के अनुसार कानून पुलिस को चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई करने का अधिकार देता है। सबसे पहले उपनिरीक्षक या उससे वरिष्ठ अधिकारी किसी भी गैर-कानूनी जमावड़े अथवा शांति भंग करने की आशंका वाले समूह को तितर-बितर होने का आदेश दे सकता है। यदि भीड़ आदेश का पालन नहीं करती तो उसे हटाने के लिए पुलिस आवश्यक बल का प्रयोग कर सकती है, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर गिरफ्तारी भी शामिल है। कानून पुलिस को केवल उतना ही बल प्रयोग करने की अनुमति देता है, जितना परिस्थितियों में आवश्यक हो। इसे ग्रेडेड रिस्पांस कहा जाता है। इसका अर्थ है कि पुलिस सीधे कठोर बल का प्रयोग नहीं करती। पहले समझाइश, सार्वजनिक घोषणा और चेतावनी दी जाती है।

यदि उससे भी स्थिति नियंत्रित न हो तब वाटर कैनन, आंसू गैस तथा अन्य गैर-घातक उपाय अपनाए जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर सीमित लाठीचार्ज किया जा सकता है। इसके बाद भी यदि भीड़ हिंसक बनी रहे और लोगों के जीवन अथवा सार्वजनिक संपत्ति के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करे, तभी रबर बुलेट, प्लास्टिक पैलेट अथवा पंप-एक्शन एंटी-रायट गन जैसे विशेष उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता है। इन उपकरणों का उद्देश्य किसी व्यक्ति की जान लेना नहीं, बल्कि हिंसक भीड़ को नियंत्रित करना और ऐसी स्थिति से बचना है, जहां वास्तविक गोलियों का प्रयोग करना पड़े। फिर भी, इनका उपयोग केवल प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा निर्धारित एसओपी के अनुसार ही किया जाना चाहिए। यदि इन उपायों के बाद भी स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए, तभी कानून विशेष परिस्थितियों में सशस्त्र बलों की सहायता लेने की अनुमति देता है। सामान्यतः ऐसी कार्रवाई कार्यपालक मजिस्ट्रेट के निर्देशन में की जाती है।

यदि किसी आपात स्थिति में मजिस्ट्रेट उपलब्ध न हो, तो कानून वरिष्ठतम उपनिरीक्षक अथवा उससे उच्च अधिकारी तथा सशस्त्र बलों के राजपत्रित अधिकारी को भी आवश्यक परिस्थितियों में आग्नेयास्त्रों के प्रयोग का आदेश देने का अधिकार प्रदान करता है। पैलेट आधारित भीड़ नियंत्रण प्रणाली भारत में लगभग दो दशकों से प्रचलन में है। जम्मू-कश्मीर में लंबे समय तक चले हिंसक पथराव के दौरान इसका उपयोग व्यापक चर्चा का विषय बना। व्यावहारिक दृष्टि से यह भीड़ नियंत्रण के सामान्य उपायों और घातक हथियारों के बीच का एक मध्यमार्गी विकल्प माना जाता है। स्पष्ट है कि कानून पुलिस को हिंसक एवं गैर-कानूनी भीड़ के विरुद्ध बल प्रयोग का अधिकार देता है। हालांकि बल का प्रयोग सदैव न्यूनतम, आवश्यक, अनुपातिक तथा अंतिम विकल्प के रूप में ही किया जाए। पुलिस का उद्देश्य नागरिकों को पराजित करना नहीं, बल्कि कानून का शासन स्थापित करते हुए शांति, जन-जीवन और सार्वजनिक सुरक्षा की रक्षा करना है।

पुलिस अधिकारी के लिए दंगा नियंत्रण कभी आसान निर्णय नहीं होता। ऐसी परिस्थितियों में यदि पुलिस निष्क्रिय रहे तो वही समाज उससे पूछता है कि उसने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई। फिर भी, यदि कोई अधिकारी कानून की सीमा से बाहर जाकर कार्य करता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई के भी पर्याप्त प्रविधान हैं। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पुलिसकर्मी भी इसी समाज का हिस्सा हैं। वे भी परिवार वाले नागरिक हैं, जो संविधान और कानून के प्रति अपनी शपथ का निर्वहन कर रहे होते हैं। प्रदर्शन के नाम पर पुलिस पर हमला, उनके वाहन जलाना अथवा उनकी जान को खतरे में डालना केवल किसी व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि राज्य की विधिक व्यवस्था और कानून के शासन को चुनौती देना है।

अशोक कुमार
(लेखक उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक रहे हैं)

जेन-जी और जेन-अल्फा ने बढ़ाई संघ और भाजपा की चिंता

देश की राजनीति में पिछले कुछ सप्ताह के घटनाक्रम ने यह संकेत दिया है। राजनीतिक दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल विपक्ष नहीं, बल्कि देश का युवा वर्ग भी बनता जा रहा है। जेन-जी और जेन-अल्फा ऐसे दौर में खड़े हैं, जहां उनकी प्राथमिकताएं धर्म, जाति और भावनात्मक मुद्दों से अधिक शिक्षा, रोजगार, परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और भविष्य की चिंता है। यही कारण है, छात्र आंदोलनों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। छात्र आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत का स्वयं सामने आना राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण घटना मानी जा रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, यदि समय रहते युवा वर्ग की नाराजगी दूर नहीं की गई तो आने वाले वर्षों में भारी नुकसान हो सकता है। भाजपा की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत, धार्मिक ध्रुवीकरण थी, वह अपना प्रभाव खो सकती है। हर घर में पढ़ने वाला छात्र है, हर परिवार में रोजगार की चिंता है। प्रत्येक परिवार को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। यही चिंता अब सड़कों पर दिखाई देने लगी है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा युवाओं को कॉकरोच कहे जाने की कथित टिप्पणी के बाद जो विवाद खड़ा हुआ है, उसने छात्र असंतोष को अधिक उग्र बना दिया है। अभिजीत दीपके द्वारा गठित कॉकरोच जनता पार्टी और उसके आंदोलनों ने राजनीतिक परिस्थितियों को नई दिशा दे दी है। माना जा रहा है, प्रारंभ में इस आंदोलन को नियंत्रित दायरे में रखने की जो रणनीति भाजपा ने बनाई थी, वह पूरी तरह से विफल हो गई है। घटनाक्रम पूरी तरह से जो सोचा गया था, वह उलटा पड़ गया है। पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता, भ्रष्टाचार और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर शुरू हुआ आंदोलन 20 जुलाई के संसद चलो अभियान के बाद राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस, पेलट गन और पुलिस की कथित बर्बरतापूर्ण कार्रवाई ने आंदोलन को पेपर लीक मुद्दे और शिक्षा के मुद्दे तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि उसे केंद्र सरकार के खिलाफ व्यापक असंतोष में बदल दिया है। देशभर में लगभग 200 स्थानों पर हुए प्रदर्शनों ने यह स्पष्ट कर दिया है। युवा अब केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। संगठित होकर वह अपनी बात मनवाने के लिए सड़कों पर आने की क्षमता भी रखता है। इस दौरान भाजपा और संघ से जुड़े कई नेताओं के बयानों ने आंदोलन की आग में घी डालने का काम किया है। आंदोलन की आग को और भड़का दिया है। आंदोलनकारियों को राष्ट्रविरोधी, गैर-जिम्मेदार अथवा अन्य आपत्तिजनक विशेषणों से सत्ता पक्ष के द्वारा संबोधित करने के प्रयासों ने युवाओं की नाराजगी कम करने के बजाय उसे और बढ़ा दिया है। यही वह मोड़ था, जहां संघ को चिंता हुई और उसे अपनी रणनीति बदलने की आवश्यकता महसूस हुई।

मुंबई में संघ प्रमुख मोहन भागवत का संविधान, बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेडकर, आरक्षण तथा युवाओं के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक प्रश्नों पर खुलकर बोलना, केवल वैचारिक वक्तव्य नहीं है। संघ और उसके अनुवांशिक संगठनों की एक मजबूरी भी बन गई है। मोहन भागवत का यह कार्यक्रम एक राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। उन्होंने युवाओं की जिज्ञासाओं और प्रश्नों को लोकतांत्रिक संवाद का हिस्सा बताया। यह बदलाव इस बात का संकेत है, संघ और भाजपा अब टकराव की बजाय संवाद की रणनीति अपनाने की कोशिश कर रहा है। इसमें संघ कितना सफल होगा कहना मुश्किल है। संघ के संगठन में गोपनीयता और विचारों की अभिव्यक्ति की सीमित छूट होती है। वर्तमान युवा असीमित ज्ञान और असीमित इच्छाओं के साथ सड़कों पर उतरा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, राहुल गांधी लगातार पेपर लीक, बेरोजगारी और शिक्षा जैसे मुद्दों को उठाकर युवा वर्ग में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। युवाओं का यह वर्ग धार्मिक ध्रुवीकरण से हटकर रोजगार, शिक्षा और आर्थिक अवसरों को लेकर राहुल गांधी से प्रभावित हो रहा है। इसका असर आगामी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मतदान का आधार बनाता है, तो भारतीय राजनीति का पूरा विमर्श ही बदल सकता है। इस समय संघ और भाजपा दोहरे संकट से गुजर रही है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा और चंदा चोरी का मामला भी सुर्खियों में है। जिसने धार्मिक ध्रुवीकरण को प्रभावित किया है। युवा सपनों के भरोसे नहीं, परिणामों के आधार पर निर्णय लेते हैं। महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा आज उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। केवल बड़े वादों, भावनात्मक नारों और वैचारिक आधार पर अब युवा वर्ग मानने वाला नहीं। सरकारों और संवैधानिक संस्थाओं को पारदर्शी परीक्षा प्रणाली, रोजगार सृजन, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, महंगाई और भ्रष्टाचार इत्यादि में ठोस पारदर्शी सक्षम परिणाम देने होंगे। इतिहास गवाह है, जब युवा संगठित होकर अपने भविष्य के प्रश्नों के साथ खड़ा होता है, तो राजनीति की दिशा बदल जाती है। जेन-जी और जेन-अल्फा को केवल चुनावी गणित से नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की निर्णायक शक्ति के रूप में देखना होगा। आने वाले समय में यह तय होगा, सत्ता उनकी आकांक्षाओं को वास्तविक नीतियों में बदलती है, या सपना ही दिखाती है। युवाओं का वर्तमान असंतोष भारतीय राजनीति का नया इतिहास बनाने जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समय रहते युवाओं की बीमारी को पहचान लिया है। इसके लिए संघ और भाजपा को स्वयं मे एक बड़े बदलाव की जरूरत है। समय रहते यदि वह बदलाव कर पाते हैं, तभी सत्ता में बने रह सकते हैं।

लेखक- सनत जैन

सुविधा नहीं, गरीब के जीवन का आधार है राशन व्यवस्था

भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। विकास, डिजिटलीकरण और कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा देशभर में होती है, लेकिन क्या यह योजनाएं देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक समान रूप से सभी को लाभान्वित करती हैं? इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है. जबकि हकीकत यह है कि आज भी बिहार जैसे राज्यों के कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं, जहां हजारों गरीब परिवारों को राशन जैसी सुविधा समय पर नहीं मिल पाती है.

जिन घरों की आय इतनी कम है कि रोज कमाकर रोज खाना बनता है, उनके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। जब राशन समय पर नहीं मिलता, कम मात्रा में मिलता है या बिना किसी स्पष्ट कारण के राशन कार्ड से किसी सदस्य का नाम काट दिया जाता है, तब इसका सबसे बड़ा असर उन परिवारों पर पड़ता है जिनके लिए दो वक़्त का भरपेट भोजन जुटाना भी किसी चुनौती से कम नहीं है।

बिहार के कई ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार रहते हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करते हैं। खेतिहर मजदूर, दिहाड़ी श्रमिक, भूमिहीन किसान और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग अक्सर अनिश्चित आय पर निर्भर रहते हैं। बरसात, बाढ़, सूखा या बीमारी जैसे हालात उनकी कमाई को और प्रभावित कर देते हैं। ऐसे समय में सरकारी राशन ही उनके घर का चूल्हा जलाए रखने का सबसे भरोसेमंद सहारा बनता है। यदि किसी महीने राशन मिलने में देरी हो जाए, तो परिवार को भूखे पेट सोने की नौबत तक आ जाती है।

एक आंकड़े के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 8.7 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अनुसार, लगभग 2 करोड़ से अधिक राशन कार्ड राज्य में सक्रिय हैं, जिनके माध्यम से पात्र परिवारों को हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न (चावल और गेहूँ) अत्यंत रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाता है। वहीं अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के अंतर्गत आने वाले अत्यंत गरीब परिवारों को प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है। यही व्यवस्था लाखों परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है।

राशन कार्ड का महत्व केवल अनाज प्राप्त करने तक सीमित नहीं है। आज यह अनेक सरकारी योजनाओं तक पहुँच का महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है। पात्र परिवारों को राशन मिलने के साथ-साथ कई मामलों में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ भी मिलता है। इसके अतिरिक्त कई सरकारी योजनाओं में पात्रता निर्धारित करने, पहचान प्रमाण के रूप में उपयोग करने तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने में भी राशन कार्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही कारण है कि यदि किसी व्यक्ति या परिवार का नाम राशन कार्ड से हट जाता है, तो उसका प्रभाव केवल भोजन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और अन्य सरकारी सुविधाओं पर भी पड़ता है।

स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब नाम दोबारा जुड़वाने के लिए गरीब परिवारों को अनावश्यक खर्च या रिश्वत देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जिन लोगों के पास अपने बच्चों की पढ़ाई, दवा या भोजन के लिए पैसे नहीं होते, वे केवल अपने अधिकार को वापस पाने के लिए उधार लेकर भी रकम खर्च करने को विवश हो जाते हैं। यह केवल प्रशासनिक लापरवाही का मामला नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा करता है जो सबसे कमजोर लोगों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। मुजफ्फरपुर सहित बिहार के कई ग्रामीण इलाकों में यह शिकायत भी सामने आती है कि उचित मूल्य की दुकानों पर राशन वितरण की तिथि को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दी जाती। कहीं मशीन खराब होने का बहाना बनाया जाता है तो कहीं खाद्यान्न समय पर नहीं पहुँचने की बात कही जाती है। कई लाभार्थियों को कई बार दुकान तक आना-जाना पड़ता है। रोज मजदूरी करने वाले लोगों के लिए यह केवल आने-जाने का खर्च नहीं, बल्कि पूरे दिन की मजदूरी का नुकसान भी होता है। यदि एक व्यक्ति राशन लेने के लिए दो या तीन दिन तक काम छोड़ता है, तो उसके परिवार की आय पर सीधा असर पड़ता है। डिजिटल व्यवस्था लागू होने के बाद पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिशें अवश्य हुई हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी समस्याएं भी सामने आती हैं। आधार प्रमाणीकरण में दिक्कत, इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी, बायोमेट्रिक मशीन का सही तरीके से काम न करना या बुजुर्गों और मेहनतकश लोगों के अंगूठे के निशान स्पष्ट न मिलने जैसी समस्याओं के कारण कई पात्र लाभार्थी राशन प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। तकनीक का उद्देश्य सुविधा देना होना चाहिए, न कि पात्र व्यक्ति के अधिकार में बाधा बनना।

यह भी समझना आवश्यक है कि खाद्य सुरक्षा केवल भूख मिटाने का प्रश्न नहीं है। पर्याप्त और नियमित भोजन मिलने से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर होता है, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है तथा परिवार आर्थिक संकट के समय भी सम्मान के साथ जीवन जी पाता है। इसके विपरीत यदि राशन व्यवस्था कमजोर होती है, तो कुपोषण, कर्ज, असुरक्षा और सामाजिक असमानता जैसी समस्याएं और गहरी हो जाती हैं।

सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अनेक सुधार किए हैं। 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' जैसी व्यवस्था से प्रवासी मजदूरों को देश के किसी भी हिस्से में राशन प्राप्त करने की सुविधा मिली है। ई-पीओएस मशीनों और ऑनलाइन निगरानी प्रणाली से पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास भी हुआ है। फिर भी इन व्यवस्थाओं का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब अंतिम व्यक्ति तक समय पर, बिना भेदभाव और बिना भ्रष्टाचार के खाद्यान्न पहुँचे। जब तक हर गरीब परिवार को बिना बाधा, सम्मान पूर्वक और समय पर उसका राशन नहीं मिलेगा, तब तक खाद्य सुरक्षा का उद्देश्य अधूरा ही रहेगा।

श्रुति कुमारी
मुजफ्फरपुर, बिहार

आलेख

संसदीय-गतिरोध से नहीं चलेगा लोकतंत्र, संवाद ही है समाधान

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति उसकी संसद है। यही वह सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच है जहां राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य से जुड़े विषयों पर गंभीर विमर्श होता है, सरकार जवाबदेह बनती है, विपक्ष जनभावनाओं को स्वर देता है और कानूनों के माध्यम से देश के विकास की दिशा तय होती है। लेकिन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज संसद संवाद और सहमति का मंच बनने के बजाय टकराव, आरोप-प्रत्यारोप, नारेबाजी और राजनीतिक हठधर्मिता का अखाड़ा बनती जा रही है। मानसून सत्र में जिस प्रकार लगातार गतिरोध बना हुआ है, उससे केवल संसदीय कार्यवाही ही बाधित नहीं हो रही, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा भी आहत हो रही है। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजू और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच गतिरोध समाप्त करने के लिए हुई बातचीत भी किसी ठोस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकी। यह स्थिति बताती है कि दोनों पक्ष अपने-अपने राजनीतिक आग्रहों में इतने उलझ गए हैं कि राष्ट्रहित पीछे छूट गया है। विपक्ष की ओर से यह शर्त रखी जा रही है कि जब तक कुछ विशेष मुद्दों पर सरकार सदन में बयान और चर्चा के लिए तैयार नहीं होती, तब तक संसद की कार्यवाही नहीं चलने दी जाएगी। दूसरी ओर सरकार भी अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने पर अडिग है। परिणाम यह है कि संसद का बहुमूल्य समय निरर्थक विवादों की भेंट चढ़ रहा है।

लोकतंत्र में असहमति स्वाभाविक है, किंतु असहमति को अराजकता में बदल देना लोकतांत्रिक संस्कृति नहीं है। विपक्ष का दायित्व केवल विरोध करना नहीं, बल्कि रचनात्मक सुझाव देना भी है। सरकार को कठघरे में खड़ा करना विपक्ष का अधिकार है, परंतु संसद को ठप कर देना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। लोकतंत्र में विरोध की भी मयार्दा होती है। जब विरोध संसद को चलने ही न दे, तब वह लोकतांत्रिक अधिकार नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक दायित्वों की उपेक्षा बन जाता है। पिछले कुछ वर्षों से यह चिंताजनक प्रवृत्ति लगातार बढ़ी है कि संसद सत्र प्रारंभ होने से पहले ऐसे मुद्दे राजनीतिक रूप से उछाले जाते हैं, जिनके आधार पर पूरे सत्र को बाधित किया जा सके। परिणामस्वरूप अनेक महत्वपूर्ण विधेयक बिना पर्याप्त चर्चा के पारित हो जाते हैं अथवा कई विधेयक लंबित रह जाते हैं। इससे सबसे अधिक नुकसान देश को होता है। संसद का प्रत्येक मिनट करोड़ों रुपये की सार्वजनिक धनराशि से संचालित होता है। यदि वह समय केवल शोर-शराबे और नारेबाजी में बीत जाए तो यह करदाताओं के धन और लोकतांत्रिक विश्वास-दोनों का अपमान है।

लोकतंत्र में संवाद ही समाधान का सबसे प्रभावी माध्यम है। महात्मा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक भारतीय राजनीति की श्रेष्ठ परंपरा संवाद, सहमति और संवेदनशीलता की रही है। आज

आवश्यकता इस बात की है कि पक्ष और विपक्ष दोनों अपने-अपने दुराग्रह छोड़कर संवाद की मेज पर बैठें। संसद की गरिमा इस बात में नहीं कि कौन किसे अधिक कठघरे में खड़ा करता है, बल्कि इस बात में है कि राष्ट्रहित के प्रश्नों पर कितनी गंभीरता से विचार किया जाता है। विशेष रूप से कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी को यह समझना होगा कि लोकतंत्र केवल आंदोलन और विरोध का नाम नहीं है। विपक्ष की भूमिका सरकार को गिराने की नहीं, बल्कि लोकतंत्र को संभालने की होती है। यदि प्रत्येक मुद्दे पर संसद को बाधित करने की रणनीति अपनाई जाएगी तो जनता के बीच यह संदेश जाएगा कि विपक्ष के पास वैकल्पिक नीति और दृष्टि का अभाव है। लोकतंत्र में जनता केवल विरोध नहीं, समाधान भी चाहती है। यदि विपक्ष स्वयं संवाद से दूरी बनाएगा तो ह्यसंवाद से समाधानह्न का आदर्श केवल नारा बनकर रह जाएगा।

सरकार की भी जिम्मेदारी कम नहीं है। लोकतंत्र में बहुमत का अर्थ मनमानी नहीं होता। सरकार को भी विपक्ष की उचित मांगों को सुनना चाहिए और जहां संभव हो, सहमति का मार्ग निकालना चाहिए। संसद किसी एक दल की नहीं, पूरे राष्ट्र की संस्था है। इसलिए सरकार को भी संवेदनशीलता, धैर्य और व्यापक दृष्टिकोण का परिचय देना होगा। किंतु यदि संवाद का प्रत्येक प्रयास केवल राजनीतिक शर्तों और हठधर्मिता में उलझ जाए तो समाधान की संभावनाएं स्वत: समाप्त हो जाती हैं। आज सबसे बड़ी आवश्यकता राजनीतिक परिपक्वता की है। दुर्भाग्य से भारतीय राजनीति में आग्रह, पूर्वाग्रह और दुराग्रह का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। हर मुद्दे को चुनावी लाभ-हानि के चश्मे से देखा जा रहा है। संसद में बहस कम और राजनीतिक संदेश अधिक दिए जा रहे हैं। यह प्रवृत्ति लोकतंत्र को कमजोर करती है। संसद का उद्देश्य जनकल्याणकारी नीतियों पर विचार करना है, न कि चुनावी रणनीतियों का मंच बन जाना।

देश आज आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति, रोजगार, शिक्षा, कृषि, राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और सामाजिक समरसता जैसी अनेक चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय संसद का प्रत्येक दिन अत्यंत मूल्यवान है। यदि यह समय केवल राजनीतिक टकराव में व्यतीत होगा तो विकास की गति अवश्य प्रभावित होगी। कानूनों में विलंब, नीतिगत निर्णयों की देरी और संसदीय अस्थिरता का सीधा प्रभाव आम नागरिक के जीवन पर पड़ता है। भारतीय लोकतंत्र की मजबूती इस बात में नहीं कि संसद में कितना शोर हुआ, बल्कि इस बात में है कि वहां कितने सार्थक विचार सामने आए। स्वस्थ लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष प्रतिद्वंद्वी अवश्य होते हैं, किंतु शत्रु नहीं। दोनों का अंतिम लक्ष्य राष्ट्रहित होना चाहिए। यदि राजनीतिक दल इस मूल भावना को भूल जाएंगे तो लोकतंत्र केवल संख्या का खेल बनकर रह जाएगा।

आज आवश्यकता इस बात की है कि सभी राजनीतिक दल आत्ममंथन करें। विपक्ष अपने विरोध को रचनात्मक बनाए, सरकार अपने संवाद को व्यापक बनाए और दोनों मिलकर संसद की प्रतिष्ठा पुन: स्थापित करें। लोकतंत्र का भविष्य टकराव में नहीं, संवाद में सुरक्षित है। संसद की गरिमा नारेबाजी से नहीं, विचार-विमर्श से बढ़ती है। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में यदि संसद ही गतिरोध का प्रतीक बन जाएगी तो जनता का विश्वास कमजोर होगा, जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए शुभ संकेत नहीं है। समय की पुकार है कि राजनीति चुनावों की सीमाओं से ऊपर उठकर राष्ट्रनिर्माण की दिशा में आगे बढ़े। पक्ष और विपक्ष दोनों यह स्मरण रखें कि वे किसी दल के नहीं, पहले भारत के प्रतिनिधि हैं। संसद की प्रत्येक घड़ी राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है। उसे हठ, अहंकार और राजनीतिक स्वार्थ की भेंट चढ़ाना भविष्य की पीढ़ियों के साथ अन्याय होगा। यदि लोकतंत्र को सशक्त बनाना है, संसद की प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित करनी है और भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो केवल एक ही मार्ग है-संवाद, सहमति और राष्ट्रहित। यही भारतीय लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति है और यही संसदीय मयार्दा का सर्वोच्च आदर्श।

लेखक – ललित गर्ग
(लेखक, पत्रकार, स्तंभकार)
(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

संक्षिप्त वार्ता

दिल्ली में युवती का मोबाइल फोन छीनकर भागे तीन युवक गिरफ्तार

नई दिल्ली, 08 अगस्त (वेब वार्ता)। दिल्ली के सोनिया विहार पुलिस ने युवती का मोबाइल फोन छीनकर भागे तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान रेहान (22), मोहम्मद कैफ (22) और फहाद (22) के रूप में हुई है। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से अपराध में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस जांच में सामने आया है कि इन तीनों आरोपियों के खिलाफ पहले कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। इसके बाद भी पुलिस पूरे मामले की विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है।

पुलिस के मुताबिक, शिकायतकर्ता रेनू शर्मा ने बताया कि जब वो सोनिया विहार के पांचवे पुश्ते की ओर जा रहे थे, तभी तीन लोगों ने उसका मोबाइल फोन छीन लिया और मौके से फरार हो गए। इसके बाद पीड़िता पुलिस थाने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पहुंची। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और पीड़िता को आश्वस्त किया कि उसका मोबाइल उसे वापस मिलेगा और इस घटना में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

आप ने दिल्ली में गाद निकासी में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप

नई दिल्ली, 08 अगस्त (वेब वार्ता)। आम आदमी पार्टी (आप) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने राष्ट्रीय राजधानी में नालों से गाद निकालने के काम में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद नालों की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ और पैसा केवल कागजों में ही खर्च किया गया।

सौरभ भारद्वाज ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि गाद निकालने के नाम पर बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है और कई नाले वास्तव में साफ नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि गाद निकालने से जुड़े काम का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए। इसके बावजूद लिखित रूप से मांग किए जाने के बाद भी थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं कराया गया। भारद्वाज ने कहा कि इस साल भी अब तक ऑडिट के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

दिल्ली में कांवड़ मार्गों पर कड़ी सुरक्षा

वीएचपी-बजरंग दल के स्वयंसेवक भी संभाल रहे ड्यूटी

नई दिल्ली, 08 अगस्त (वेब वार्ता)। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कांवड़ यात्रा के रास्तों पर सुरक्षा और ट्रैफिक की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, सीआरपीएफ और विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के स्वयंसेवकों को तैनात किया गया है।

विश्व हिंदू परिषद के सह-जिला मंत्री अनमोल दुबे ने कहा, कैंप की सुरक्षा का काम विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल संभालते हैं। यमुना पार के अलग-अलग कैंपों में हमारे दो-तीन कार्यकर्ता पूरी रात सुरक्षा की ड्यूटी पर रहते हैं। क्योंकि, जैसा कि आपने हर बार देखा होगा, यहां अलग-अलग तरह के लोग आते हैं और गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हिंदू समाज की बदनामी न हो और बुरे तत्वों की वजह से कांवड़ कैंपों को कोई नुकसान या अपमान न झेलना पड़े, हमारे कार्यकर्ता यह काम करते हैं।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से शनिवार को कांवड़ शिविरों के निरीक्षण को लेकर अनमोल दुबे ने कहा कि जब से दिल्ली में सरकार बदली है, तब से माहौल भी बदल गया है। पहले लोग खाली हाथ घूमते थे। पिछले साल यहां फूलों की बारिश की गई थी। इस साल भी पुष्पवर्षा की जाएगी। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कभी फूलों की बारिश नहीं की थी, लेकिन पिछले साल दिल्ली पुलिस ने भी पुष्पवर्षा की। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी वहां मौजूद थे। शनिवार को भी यहां पुष्पवर्षा होगी।

कांवड़ यात्रा के दौरान मांस की दुकानें बंद किए जाने पर उन्होंने कहा, यात्रा के दौरान दुकानें अधिकतर बंद हैं। मौजपुर चौक के पास हमारा एक कैंप लगा है। वहां आसपास बहुत सारी मीट की दुकानें थीं। अब वे कांवड़ यात्रा के दौरान बंद हैं। अनमोल दुबे ने कांवड़ यात्रा में प्रशासन के सहयोग की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस की एक बैठक हुई थी। अब यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस का भी सहयोग मिल रहा है। दिल्ली में भी कांवड़ शिविरों के पास पुलिस प्रशासन मुस्तैद है।

महिला मरीज से अभद्रता पर एम्स का सिक्योरिटी गार्ड नौकरी से बर्खास्त

नई दिल्ली, 08 अगस्त (वेब वार्ता)। एम्स नई दिल्ली ने एक महिला मरीज के साथ कथित गलत व्यवहार की शिकायत मिलने के बाद गार्ड के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। संस्थान ने गार्ड को नौकरी से निकाल दिया है और मामले में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। एम्स प्रशासन के अनुसार, आरोपी गार्ड की पहचान धनंजय सिंह के रूप में हुई है। वह एक निजी सिक्योरिटी एजेंसी के माध्यम से एम्स में तैनात था। शिकायत सामने आने के बाद संस्थान ने उसे ड्यूटी से हटा दिया और संबंधित सिक्योरिटी एजेंसी पर जुमार्ना भी लगाया है।

650 करोड़ रुपये के दवा घोटाले में आप का आरोप, फाइलों में पहुंचीं दवाएं, अस्पतालों में नहीं

नई दिल्ली, 08 अगस्त (वेब वार्ता)। दिल्ली सरकार के कथित 650 करोड़ रुपये के दवा घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी ने दावा किया है कि अस्पतालों के लिए खरीदी गई दवाओं की आपूर्ति में भी बड़े स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं और बड़ी मात्रा में दवाएं कागजी रिकॉर्ड में अस्पतालों तक पहुंची दिखाई गईं, जबकि वास्तविक रूप से उनकी आपूर्ति नहीं हुई।

आम आदमी पार्टी के प्रदेश स्तर के नेताओं ने शनिवार को आरोप लगाया कि सरकार द्वारा खरीदी गई दवाओं का बड़ा हिस्सा अस्पतालों तक पहुंचने के बजाय सरकारी अभिलेखों में ही वितरित दिखाया गया। पार्टी के अनुसार, करीब 70 से 80 प्रतिशत दवाओं की आपूर्ति केवल कागजों में दर्ज की गई, जबकि वास्तविक रूप से लगभग 20 से 30 प्रतिशत दवाएं ही अस्पतालों तक पहुंचीं।

आप ने यह भी आरोप लगाया कि लगभग 100 करोड़ रुपये मूल्य की दवाओं की खरीद पर करीब 400 करोड़ रुपये खर्च किए गए। पार्टी का कहना है कि खरीद प्रक्रिया पर पहले से उठ रहे सवालों के बीच अब दवाओं की वास्तविक आपूर्ति और वितरण व्यवस्था भी जांच के दायरे में आनी चाहिए।

आम आदमी पार्टी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल का उदाहरण देते हुए दावा किया कि वहां लाखों रुपये मूल्य की दवाओं की आपूर्ति सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है, लेकिन अस्पताल में उनकी वास्तविक मौजूदगी नहीं मिली। पार्टी का कहना है कि इस तरह के मामलों की विस्तृत जांच से दवा खरीद और वितरण में कथित अनियमितताओं की वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मामले में केवल दवाओं की खरीद प्रक्रिया की जांच पर्याप्त नहीं है, बल्कि दवाओं के भंडारण, अस्पतालों तक पहुंचने और वितरण से संबंधित पूरे तंत्र की भी जांच की जानी चाहिए। आप ने आरोप लगाया कि यदि सरकारी रिकॉर्ड और अस्पतालों में उपलब्ध दवाओं के भंडार में अंतर पाया जाता है तो यह गंभीर प्रशासनिक अनियमितता का विषय है। पार्टी ने दवा खरीद से लेकर अस्पतालों में वितरण तक की पूरी प्रक्रिया की जांच कराने की मांग की है।

हालांकि, उपलब्ध जानकारी में दिल्ली सरकार की ओर से इन आरोपों पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया शामिल नहीं है।

दिल्ली में फुटपाथ से हटेंगे ईवी चार्जिंग स्टेशन, नई नीति के तहत 32,000 चार्जिंग बिंदु बनाने का लक्ष्य

नई दिल्ली, 08 अगस्त (वेब वार्ता)। दिल्ली में फुटपाथ पर बनाए गए विद्युत वाहनों के चार्जिंग केंद्र अब हटाए जाएंगे। सरकार ने माना है कि गलत स्थानों पर बने इन केंद्रों से पैदल यात्रियों के आवागमन में बाधा उत्पन्न होने के साथ यातायात जाम और सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ रहा है। नई ईवी नीति 2026 के तहत सरकार अब चार्जिंग ढांचे के विस्तार के साथ उसके लिए उचित स्थान सुनिश्चित करने पर भी जोर दे रही है।

दिल्ली में वर्ष 2020 में तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार ने ईवी नीति लागू की थी। उस समय राजधानी को विद्युत वाहनों के लिए अग्रणी शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि, चार्जिंग ढांचे के लिए पर्याप्त और उपयुक्त स्थानों की व्यवस्था नहीं किए जाने के कारण बाद में कई स्थानों पर फुटपाथ पर ही चार्जिंग केंद्र स्थापित कर दिए गए। सितंबर 2022 में तत्कालीन सरकार ने लोक निर्माण विभाग की 20 सड़कों के किनारे 100 चार्जिंग बिंदु स्थापित करने की अनुमति दी थी। इसके बाद कई स्थानों पर फुटपाथ पर चार्जिंग केंद्र बनाए गए। इससे पैदल चलने वालों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा तथा कुछ स्थानों पर यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई।

अब दिल्ली सरकार ने इस व्यवस्था में बदलाव का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल में स्पष्ट किया था कि भविष्य में फुटपाथ पर विद्युत वाहन चार्जिंग बिंदु स्थापित नहीं किए जाएंगे। संबंधित विभागों को सर्वे कर चार्जिंग केंद्रों के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करने के निर्देश दिए जाएंगे।

दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई को नई ईवी नीति 2026 अधिसूचित की है। इसके तहत अगले 4 वर्षों में राजधानी में विद्युत वाहन चार्जिंग बिंदुओं की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 32,000 करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का उद्देश्य विद्युत वाहनों को बढ़ावा देने के साथ-साथ चार्जिंग सुविधाओं के लिए व्यवस्थित आधारभूत ढांचा तैयार करना है। नई नीति के तहत प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी को राजस्व विभाग के साथ मिलकर चार्जिंग केंद्रों के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करने की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार चरणबद्ध तरीके से चार्जिंग केंद्रों की संख्या बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए मेट्रो और नगर निगम की पार्किंग, निर्धारित बाजार एवं माल पार्किंग, पेट्रोल पंप, बस डिपो तथा खाली सरकारी भूमि का उपयोग किया जा सकता है। अनधिकृत कॉलोनियों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर भी इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पैदल यात्रियों और यातायात की आवाजाही बाधित न हो।

दिल्ली भाजपा मनाएगी आजादी का जश्न, 9 से 15 अगस्त तक होंगे कार्यक्रम

नई दिल्ली, 08 अगस्त (वेब वार्ता)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दिल्ली प्रदेश की ओर से 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 9 से 15 अगस्त तक जिला एवं मंडल स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इनमें तिरंगा यात्रा, शहीद स्मारकों की स्वच्छता एवं माल्यार्पण, शहीद परिवारों का सम्मान, विभाजन विभीषिका दिवस तथा स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण कार्यक्रम प्रमुख हैं।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि 9 अगस्त को अंग्रेजों भारत छोड़ो दिवस से स्वतंत्रता दिवस सप्ताह की शुरूआत होगी। उन्होंने कहा कि सप्ताह भर दिल्ली के विभिन्न जिलों एवं मंडलों में देशभक्ति और राष्ट्रसेवा से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के संयोजन एवं संचालन की जिम्मेदारी प्रदेश महामंत्री विष्णु मित्तल को दी गई है। प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील यादव एवं सारिका जैन तथा पूर्वांचल मोर्चा अध्यक्ष संतोष ओझा सह-संयोजक के रूप में उनका सहयोग करेंगे। स्वतंत्रता दिवस सप्ताह की शुरूआत 9 अगस्त को सुबह 9:30 बजे सांसद बांसुरी स्वराज मालवीय नगर में पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर करेंगी।

दिल्ली सरकार ने सुनिश्चित किया कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े: गुप्ता

नई दिल्ली, वेब वार्ता

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी के दिलशाद गार्डन इलाके में दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा के निकट स्थित एक कांवड़ शिविर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि कांवड़ियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

गुप्ता ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, चाहे वित्तीय सहायता हो, सफाई व्यवस्था हो या बिजली-पानी की आपूर्ति, दिल्ली सरकार ने सुनिश्चित किया कि कांवड़ शिविरों का रखरखाव बेहतर ढंग से हो। पिछले साल की

तरह इस साल भी हमारे भोले के भक्तों को किसी भी तरह की समस्या भी न हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किया गया है। दिल्ली सरकार ने कांवड़ यात्रा 2026 के लिए कांवड़ समितियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को बढ़ाने के प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे दी थी। मंत्रिमंडल के फैसले के तहत 20 हजार वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र में फैले और छह से बारह दिन तक आयोजित होने वाले कांवड़ शिविरों के लिए अब वित्तीय सहायता 15 लाख रुपये कर दी गई है।

नरेला में मर्सिडीज और वैगन-आर कार की टक्कर में बुजुर्ग महिला की मौत

नई दिल्ली, 08 अगस्त (वेब वार्ता)। दिल्ली के नरेला इलाके में शनिवार सुबह तेज रफ्तार मर्सिडीज कार की एक दूसरी गाड़ी से टक्कर हो गई, जिसमें 70 साल की एक महिला की मौत हो गई। यह घटना सुबह करीब 8 बजे नरेला के मामुरपुर में हिमालय अपार्टमेंट के सामने हुई। सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।

शुरूआती जांच के मुताबिक, एक मर्सिडीज और वैगन-आर की आमने-सामने टक्कर हुई। टक्कर से वैगन-आर पास खड़ी एक थ्री-व्हीलर लोडिंग वैन से जा टकराई। टक्कर के दौरान नरेला के मामूरपुर की रहने वालीं और सत्यनारायण की पत्नी उर्मिला (70) गाड़ियों के बीच फंस गईं। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं वैगनआर के ड्राइवर को मामूली चोटें आईं। पुलिस ने बताया कि लापरवाही से मौत और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है।

इस दुर्घटना ने एक बार फिर शहरी इलाकों में लापरवाही और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के मुद्दे की ओर ध्यान खींचा है। इसी तरह की एक घटना में 30 नवंबर 2025 को दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एम्बिएंस मॉल के पास तेज रफ्तार मर्सिडीज जी63 ने पैदल चल रहे तीन लोगों को टक्कर मार दी। पुलिस ने बताया था कि तीनों पीड़ित एम्बिएंस मॉल के एक रेस्टोरेंट में काम करते थे। उन्हें घटनास्थल पर घायल हालत में पाया गया और अस्पताल ले जाया गया। उनमें से एक उत्तराखंड के चमोली के रहने वाले 23 वर्षीय रोहित को मृत घोषित कर दिया गया था। इससे पहले 19 मई, 2024 को पुणे में नशे में धुत 17 साल के एक नाबालिग ने पोर्श कार से कल्याणी नगर इलाके में एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी, जिससे दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा की मौत हो गई थी। इस मामले ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया था और सड़क सुरक्षा, जवाबदेही और लग्जरी गाड़ियों से जुड़ी लापरवाही से गाड़ी चलाने के मुद्दों पर फिर से बहस छेड़ दी थी।

सरिता विहार में नाले में बहा 18 वर्षीय युवक, तलाश में जुटे बचाव दल

नई दिल्ली, 08 अगस्त (वेब वार्ता)। दिल्ली के सरिता विहार थाना क्षेत्र के प्रियंका कैंप इलाके में शुक्रवार शाम हुई मूसलाधार बारिश के दौरान एक 18 वर्षीय युवक नाले के तेज बहाव में बह गया। युवक की पहचान अंकित के रूप में हुई है। घटना के कई घंटे बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिल सका है। पुलिस, स्थानीय लोगों और बचाव दलों की मदद से नाले तथा आसपास के क्षेत्रों में उसकी तलाश की जा रही है। हादसे के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार, शुक्रवार शाम दिल्ली में हुई तेज बारिश के कारण प्रियंका कैंप क्षेत्र की सड़कें और गलियां पानी से लबालब हो गई थीं। इसी दौरान अंकित बारिश के पानी से भरे नाले के पास से गुजर रहा था।

देवली में पार्किंग की दीवार ढही, 8-10 वाहन क्षतिग्रस्त

नई दिल्ली, 08 अगस्त (वेब वार्ता)। दिल्ली के देवली इलाके में बारिश के बीच एक निजी पार्किंग की दीवार अचानक ढह गई। हादसे में पार्किंग में खड़े करीब 8-10 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। स्थानीय लोगों के अनुसार, इलाके के पीछे काम चल रहा था और पूरी गली खोद दी गई थी, जिसके चलते वहां पानी जमा हो गया था। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि वह करीब आठ साल से यहां वाहन पार्क कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कभी ऐसी समस्या नहीं हुई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एमसीडी की ओर से काम ठीक से नहीं किया गया। गलियां खोदी गई हैं, सीवर भरे हुए हैं और मानसून के दौरान पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है। पानी की निकासी नहीं होने के कारण दीवार ढहने की घटना हुई।

चीनी मांझे की खरीद ब्रिकी में संलिप्त पाए जाने पर आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली, 08 अगस्त (वेब वार्ता)। भारत में चीनी मांझों की खरीद-बिक्री प्रतिबंधित है। इसके बावजूद दिल्ली के सीलमपुर इलाके में पुलिस को जानकारी मिली कि कोई शख्स अवैध रूप से चीनी मांझों की खरीद-बिक्री में संलिप्त है।

पुलिस ने उसे फौरन गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मोहम्मद जमीर के रूप में हुई है। उसके पास से चीनी मांझे के 30 रोल भी बरामद हुए हैं। इसके बाद पुलिस ने इस बारे में शीर्ष पुलिस अधिकारियों को जानकारी दी गई। इसके बाद पुलिस के निर्देश पर बाकायदा एक टीम का गठन किया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने उस आरोपियों को ना महज गिरफ्तार किया, बल्कि

उसके पास 30 प्रतिबंधित चीनी मांझे की रील भी बरामद की। पुलिस उसे गिरफ्तार करके अब उससे पूछताछ करने की प्रक्रिया में जुटी हुई है, ताकि इस पूरे मामले के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाई जा सके। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, चीनी मांझे की खरीद ब्रिकी प्रतिबंधित है, जिसे देखते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223(ए) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

हालांकि, आरोपी के खिलाफ किसी भी प्रकार का आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। लेकिन, पुलिस विभिन्न पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि हमारे लिए इस पूरे मामले की विभिन्न पहलुओं से जांच करना इसलिए जरूरी हो जाता है, ताकि इस बात की जानकारी जुटाई जा सके कि प्रतिबंधित अवैध चीनी मांझे की खरीद ब्रिकी में कोई और शामिल तो नहीं है। बता दें कि भारत में चीनी मांझे की बिक्री और खरीद अवैध है। इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर उसे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत इसका उपयोग या व्यापार दंडनीय अपराध माना जाएगा। वहीं, नियमों का उल्लंघन करने पर 5 साल तक की कैद और 1 लाख रुपये तक का जुमार्ना भी हो सकता है।

दिल्ली में न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट

हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान

नई दिल्ली, 08 अगस्त (वेब वार्ता)। राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई और इस बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दिन के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है।

सफदरजंग मौसम केंद्र में न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.2 डिग्री कम और पिछले दिन की तुलना में 0.9 डिग्री कम है। पालम में न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले दिन से 0.7 डिग्री कम है। वहीं, लोधी रोड में न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस और आयानगर में 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले दिन की तुलना में 0.1 डिग्री कम है। शनिवार तड़के कई मौसम केंद्रों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। सफदरजंग केंद्र पर शुक्रवार रात 11:30 बजे से देर रात 2:30 बजे तक 16.6 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके बाद अगले तीन घंटों में 1.6 मिमी बारिश हुई। पालम में रात 11:30 बजे से देर रात 2:30 बजे तक 10.2 मिमी और देर रात 2:30 बजे से सुबह 5:30 बजे तक 3.4 मिमी बारिश दर्ज की गई। पूसा मौसम केंद्र में देर रात 2:30 बजे तक 13 मिमी और उसके बाद 16 मिमी बारिश दर्ज की गई।

आईएमडी ने शनिवार को बहुत हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है और कहा है कि अगले कुछ दिनों तक मौसम की ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। आईएमडी के एक अधिकारी ने बताया, ह्यह्यशनिवार को कई स्थानों पर बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है। सुबह से दोपहर तक कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। शाम या रात के समय कई इलाकों में फिर से बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार, अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। दिल्ली में अगस्त के पहले सप्ताह में 2011 के बाद सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। महीने के पहले सात दिनों में राष्ट्रीय राजधानी में 127 मिमी बारिश हुई। शुक्रवार तक लगातार बारिश के कारण शहर में अगस्त के पहले सप्ताह में 15 वर्षों की सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। शहर के कई मौसम केंद्रों पर एक दिन में 100 मिमी से अधिक बारिश दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, शनिवार सुबह दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) संतोषजनक श्रेणी में रहा। सुबह नौ बजे एक्यूआई 59 दर्ज किया गया, जबकि शुक्रवार शाम चार बजे 24 घंटे का औसत एक्यूआई 63 रहा था, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। सीपीसीबी के मानकों के अनुसार, 0-50 एक्यूआई को अच्छा, 51-100 को ह्यसंतोषजनकह्ल, 101-200 को ह्यमध्यमह्ल, 201-300 को खराब, 301-400 को ह्यबहुत खराबह्ल और 401-500 को ह्यगंभीरह्ल माना जाता है।

दिल्ली के देवली में पार्किंग की दीवार ढही: 8-10 वाहन क्षतिग्रस्त, जलभराव से हादसा; एमसीडी पर लापरवाही का आरोप

नई दिल्ली, 08 अगस्त (वेब वार्ता)। दिल्ली के देवली इलाके में बारिश के बीच एक निजी पार्किंग की दीवार अचानक ढह गई। हादसे में पार्किंग में खड़े करीब 8-10 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। स्थानीय लोगों के अनुसार, इलाके के पीछे काम चल रहा था और पूरी गली खोद दी गई थी, जिसके चलते वहां पानी जमा हो गया था।

एक स्थानीय निवासी ने बताया कि वह करीब आठ साल से यहां वाहन पार्क कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कभी ऐसी समस्या नहीं हुई। स्थानीय लोगों का

आरोप है कि एमसीडी की ओर से काम ठीक से नहीं किया गया। गलियां खोदी गई

हैं, सीवर भरे हुए हैं और मानसून के दौरान पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है। पानी की निकासी नहीं होने के कारण दीवार ढहने की घटना हुई।

नहर के पास मिला युवक का शव

नई दिल्ली, 08 अगस्त (वेब वार्ता)। समयपुर बादली के बड़ा खेड़ा नहर पुल के पास एक युवक का शव मिला है। 30 साल के युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। उसके पास से कोई दस्तावेज नहीं मिला है। पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर उसकी पहचान करने में जुटी है। उसके दाहिने हाथ पर ओम नमः शिवाय, शेर और त्रिशूल के टैटू बने हैं। पुलिस इन टैटू को पहचान के लिए अहम मान रही है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पहचान के प्रयास कर रही है।

संक्षिप्त वार्ता

82 वर्षीय बंदी हकीक की देवरिया जेल में मृत्यु

वेब वार्ता, देवरिया

देवरिया जिले में भूमि विवाद से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में जिला कारागार में निरुद्ध 82 वर्षीय बंदी की गुरुवार को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मृत्यु हो गई। बंदी को आनन-फानन में महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मेडिकल कॉलेज पहुंचे मृतक के पुत्र एजाज व परिजनों ने जेल में उपचार में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। वहीं जेल प्रशासन ने आरोपों को निराधार बताते हुए बंदी की तबीयत बिगड़ते ही तत्काल चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने की बात कही। पुलिस के अनुसार मृतक हकीक पुत्र मोहम्मदीन अंसारी निवासी भटवा, थाना चौरा खास (पूर्व में पटहेरवा), जनपद कुशीनगर का रहने वाला था। वह मधुमेह और उच्च रक्तचाप से पीड़ित था। गुरुवार को दोपहर में उसने पेट दर्द और तबीयत खराब होने की शिकायत बंदी रक्षकों से की।

सूचना मिलते ही जेल चिकित्सक अशीष रंजन व जेल के डॉक्टर राहुल त्रिपाठी मौके पर पहुंचे और बंदी का प्राथमिक उपचार किया गया। हालत में सुधार न होने पर एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। जिसकी सूचना पुलिस प्रशासन ने दी है। पुलिस के अनुसार हकीक को भूमि विवाद में धोखाधड़ी के एक मामले में 27 जुलाई को जिला कारागार भेजा गया था। यह मुकदमा 29 अक्टूबर 2025 को कोतवाली में दर्ज हुआ था। इसी मामले में उसका भाई रफीक भी जिला कारागार में निरुद्ध है। इस संबंध में जेल अधीक्षक ने बताया कि बंदी की तबीयत खराब होने की सूचना मिलते ही तत्काल चिकित्सकीय उपचार कराया गया और बिना विलंब किए मेडिकल कालेज पहुंचाया गया। उन्होंने मृतक के परिजनों के आरोपों को निराधार बताया। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

देवरिया में हत्या के मामले में मां-बाप और बेटे को आजीवन

वेब वार्ता, देवरिया

देवरिया जिले में हत्या और जानलेवा हमले के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश जगन्नाथ की अदालत ने गुरुवार को तीन आरोपितों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने प्रभु दयाल गुप्ता, उनकी पत्नी मीना देवी और पुत्र सचिन गुप्ता पर प्रत्येक को 1.12 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 8 फरवरी 2021 की शाम करीब छह बजे खामपार बाजार के रहने वाले दिनेश गुप्ता अपने घर के बाहर बैठे थे। इसी दौरान उनके पट्टीदार प्रभु दयाल गुप्ता, मीना देवी और सचिन गुप्ता कुदाल व लाठी-डंडे लेकर पहुंचे और दिनेश पर हमला कर दिया। शोर सुनकर बचाने पहुंचे उनके भाई कुंज बिहारी गुप्ता पर भी आरोपितों ने प्राणघातक हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उपचार के दौरान दिनेश गुप्ता की मौत हो गई। घटना के बाद कुंज बिहारी गुप्ता की पत्नी इंद्रकला की तहरीर पर खामपार थाने में हत्या और जानलेवा हमले सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।

डीएम ने थामा तिरंगा, खिलाड़ियों के साथ निकली यूथ कनेक्ट रैली

वेब वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई : युवाओं में राष्ट्रप्रेम और देशभक्ति की भावना को और प्रबल करने के उद्देश्य से शनिवार को स्पोर्ट्स स्टेडियम से यूथ कनेक्ट तिरंगा रैली निकाली गई। जिलाधिकारी अनुनय झा ने हाथ में तिरंगा लेकर रैली का नेतृत्व किया। रैली में करीब 250 खिलाड़ियों के साथ एनसीसी कैडेट और प्रांतीय रक्षक दल के जवान शामिल हुए।

रैली के शुभारंभ से पहले क्रीड़ाधिकारी मंजू शर्मा ने जिलाधिकारी को पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत किया। इसके बाद जिलाधिकारी ने तिरंगा लहराकर रैली को महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज के लिए रवाना किया। खिलाड़ियों और युवाओं ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाए। इससे पूरा वातावरण राष्ट्रप्रेम से ओतप्रोत हो गया। स्पोर्ट्स स्टेडियम से शुरू हुई रैली महाराणा प्रताप डिग्री कॉलेज पहुंची, जहां राष्ट्रगान के साथ इसका समापन हुआ। इसके बाद प्रतिभागियों को जलपान वितरित किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने युवाओं और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका पर जोर दिया।

देवरिया में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब

वेब वार्ता, देवरिया

पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से सरयू नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। शनिवार को नदी का जलस्तर खतरे के निशान से महज 10 सेंटीमीटर नीचे पहुंच गया। जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए तटवर्ती गांवों के लोगों में बाढ़ की आशंका को लेकर भय व्याप्त है। हालांकि बाढ़ खंड और तहसील प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए तैयारियां पूरी होने का दावा किया है। केंद्रीय जल आयोग तुतीपार के अनुसार शनिवार शाम चार बजे सरयू नदी का जलस्तर 63.90 मीटर दर्ज किया गया। नदी का खतरे का निशान 64.010 मीटर है। पिछले 24 घंटे में नदी के जलस्तर में करीब 20 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। जलस्तर बढ़ने से नदी के आसपास के निचले इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। सरयू के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए भागलपुर, देवसिया, नरियांव, मईल, मईलौटा, नरसिंह डाढ़, तेलियां कला, बलिया उत्तर, बलिया दक्षिण, सहियागढ़, तकिया, धराहरा और आदर्श नगर समेत अन्य तटवर्ती गांवों के लोग बाढ़ की आशंका से भयभीत हैं। ग्रामीण लगातार नदी के जलस्तर पर नजर बनाए हुए है। बाढ़ खंड के अधिकारियों और तहसील प्रशासन की ओर से स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है। संभावित बाढ़ को देखते हुए राहत एवं बचाव कार्य से संबंधित तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

दावों की पोलः एम्स और एसजीपीजीआई जैसी सुविधाओं का ढिंढोरा, पर दो दशकों से नहीं बदला बुनियादी ढांचा

खोखले दावों के बीच कराहता हैलट जच्चा-बच्चा अस्पताल

कानपुर। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध अपर इंडिया शुगर एक्सचेंज मैटरनिटी हॉस्पिटल (हैलट जच्चा-बच्चा अस्पताल) की तस्वीर बदलने के दावे एक बार फिर शुरू हो गए हैं।

वेब वार्ता, हरी शंकर शर्मा

नव-नियुक्त विभागाध्यक्ष डॉ. सीमा द्विवेदी ने अस्पताल की सूरत संवारने का खाका तैयार कर प्राचार्य प्रो. डॉ. संजय काला को प्रस्ताव भेजा है। हालांकि, कागजी प्रस्तावों से इतर जमीनी हकीकत यह है कि अस्पताल का सिस्टम खुद वेंटीलेटर पर है। बाहरी सुंदरीकरण की कवायद के पीछे अंदर की व्यवस्था पूरी तरह जंग खा चुकी है।

3 बेड पर सिर्फ एक पंखा, नारकीय स्थिति में मरीज

बीते एक दशक में कई विभागाध्यक्ष और प्रमुख अधीक्षक (सीएमएस) आए और चले गए, लेकिन किसी ने भर्ती मरीजों का दर्द महसूस नहीं किया। अस्पताल के अधिकांश वार्डों की हालत दयनीय है। इस भीषण गर्मी में तीन-तीन बेड पर सिर्फ एक पंखा नसीब हो रहा है। प्रसूताएं और नवजात गर्मी से बेहाल हैं, लेकिन प्रशासन बाहरी दिखावे में व्यस्त है और अंदरूनी अव्यवस्था से आंखें मूंदे बैठा है।

कबाड़ में तब्दील बुनियादी ढांचा, खोखले साबित हो रहे दावे

एक तरफ जीएसवीएम प्रशासन एम्स और एसजीपीजीआई जैसी विश्वस्तरीय सुविधाएं देने की शेखी बघार रहा है, वहीं दूसरी तरफ जच्चा-बच्चा अस्पताल के सभागार ओल्ड शिफा के पास सालों पुराना कबाड़ लगा हुआ है। पिछले दो दशकों से सड़ रहे बेड और टूटे उपकरण अस्पताल प्रबंधन की अनदेखी की गवाही दे रहे हैं।

नया आश्वासन, पर कब बदलेगी हकीकत ?

1 अगस्त, 2026 को पदभार ग्रहण करने वालीं विभागाध्यक्ष डॉ. सीमा द्विवेदी ने बताया कि मरीजों को भटकने से बचाने के लिए हेल्प डेस्क और तीमारदारों के लिए अलग विश्राम स्थल का खाका तैयार कर भेजा गया है। उन्होंने कर्मचारियों की कार्यशैली और आचरण में सुधार का दावा भी किया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या यह प्रस्ताव भी पुरानी फाइलों की तरह धूल फांकेगा या वास्तव में मरीजों को इस बदहाली से निजात मिलेगी?

रात होते ही राम भरोसे वार्ड, घंटों कराहते रहते हैं मरीज

हैलट जच्चा-बच्चा अस्पताल में देर रात किसी मरीज की तबीयत बिगड़ने का मतलब है आफत को दावत देना। इमरजेंसी स्थिति में मरीज तक राहत पहुंचने में आधा घंटे से लेकर दो घंटे तक का वक्त लग जाता है। रात की ड्यूटी में अधिकांश वार्डों से नर्सें नदारद रहती हैं। जूनियर डॉक्टरों (जेआर) से शिकायत करने पर वे नर्सों पर बात टालकर पल्ला झाड़ लेते हैं। इस गैर-जिम्मेदाराना ढर्रे के कारण मरीज जीवन और मौत के बीच झूलने को मजबूर हैं।

3 बेड पर एक पंखा, रात में मरीज राम भरोसे, कबाड़ में तब्दील व्यवस्था

नए विभागाध्यक्ष ने भेजे प्रस्ताव, लेकिन सालों से चल रहा आश्वासन का खेल

उमस और गर्मी से बेहाल प्रसूताएं, तीन-तीन बेड के बीच महज एक पंखा

तीन दिन तिरंगा रोशनी से जगमगाएंगे ऐतिहासिक स्थल और सरकारी भवन

वेब वार्ता, आलोक चतुर्वेदी

ललितपुर। आगामी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोहपूर्वक और गरिमापूर्ण ढंग से मनाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शुक्रवार को मुख्य विकास अधिकारी शेषनाथ चौहान की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों तथा विभिन्न विभागाध्यक्षों की बैठक हुई। बैठक में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की रूपरेखा तय करते हुए अधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गईं। सीडीओ ने निर्देश दिए कि सभी कार्यक्रमों का आयोजन पूरी भव्यता, गरिमा और राष्ट्रीय भावना के अनुरूप कराया जाए।

मुख्य विकास अधिकारी ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका एवं नगर पंचायत तथा सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित शहीदों, महापुरुषों एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं के आसपास विशेष साफ-सफाई, प्रकाश एवं अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जाएं। स्वतंत्रता दिवस पर जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया जाएगा।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 15 अगस्त को जनपद में निर्बाध विद्युत एवं पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित रहे। शहर से लेकर गांवों तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाए। अमृत सरोवरों पर गांव के अमर शहीदों एवं महापुरुषों के नाम पर पौधरोपण कराया जाए। इसके साथ ही विभिन्न स्थानों पर तिरंगा यात्राओं का आयोजन कर लोगों में देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया जाए। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा एवं सम्मान का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। बैठक में तय किया गया कि 13 से 15 अगस्त तक लगातार तीन दिनों तक सभी सरकारी भवनों, प्रमुख इमारतों तथा स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े ऐतिहासिक स्मारकों को रात्रि में तिरंगा रोशनी से प्रकाशमान किया जाएगा। इससे शहर में स्वतंत्रता दिवस का उत्सवी माहौल दिखाई देगा। 15 अगस्त की सुबह जनपद में विभिन्न महापुरुषों एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया जाएगा। इनमें पूज्य महात्मा गांधी, चन्द्रशेखर आजाद, लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीर सावरकर, बृजनन्दन किलेदार, डॉ. भीमराव आंबेडकर, कपूर्री ठाकुर, अवंतीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई और पं. परमानंद की प्रतिमाएं शामिल हैं।

राष्ट्रगान का किया जायेगा गायन

सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों तथा संस्थाओं में निर्धारित समय पर ध्वजारोहण किया जाएगा और राष्ट्रगान का भावपूर्ण गायन होगा। शिक्षण संस्थानों में भी ध्वजारोहण एवं झंडा अभिवादन के साथ विद्यार्थियों द्वारा सामूहिक रूप से राष्ट्रगान ह्यजन-गण-मनह्ल का गायन किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला कारागार, राजकीय किशोर गृह दैलवारा, राजकीय सम्प्रेक्षण गृह सिद्धनपुरा तथा मदर टेरेसा आश्रम पनारी में फल वितरण भी कराया जाएगा।

मिशन एजुकेशन का उद्देश्य हर बच्चे को शिक्षित करना : महात्मा विद्युतानंद

वेव वार्ता, लक्ष्मीकान्त पाठक

हरदोई। मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से संचालित मिशन एजुकेशन के तहत पूज्य माता श्री अमृता रावत के जन्मदिन के उपलक्ष्य में विकासखंड कोथावां के ग्राम ढाकिया कला स्थित प्राथमिक विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कक्षा एक से पांच तक के 52 बच्चों को निशुल्क लेखन सामग्री वितरित की गई। प्रत्येक बच्चे को एक पेन, एक पेंसिल, एक रबर, एक कटर और दो कॉपियां दी गईं।

मिशन एजुकेशन के जिला प्रभारी शिवम गुप्ता ने बच्चों को अभियान के उद्देश्य की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मिशन एजुकेशन का उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराकर उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देना है। अभियान के तहत बड़े इंटर कॉलेजों में बॉक्स लगाए जाते हैं, जिनमें विद्यार्थी नई कॉपी, पेन, पेंसिल, रबर, कटर आदि लेखन सामग्री दान करते हैं। एकत्रित सामग्री जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचाई जाती है। महात्मा विद्युतानंद ने कहा कि मानव उत्थान सेवा समिति अखिल भारतीय स्तर पर पंजीकृत संस्था है, जो सामाजिक कल्याण के लिए कार्य कर रही है। समिति के संस्थापक श्री सतपाल जी महाराज हैं। संस्था का आदर्श वाक्य ह्यएक राष्ट्र, एक ध्वज, एक भावनाह्ल है। उन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में मिशन एजुकेशन की पहल श्री विभू जी महाराज द्वारा शुरू की गई थी। उन्होंने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि शिक्षा के माध्यम से वे डॉक्टर, इंजीनियर और देश के सिपाही बनकर राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार और आध्यात्मिक ज्ञान भी जरूरी है। भौतिक ज्ञान के साथ संस्कार और आध्यात्मिक ज्ञान मनुष्य को महान बनाते हैं।

देवरिया में म्यूल खातों से साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह का पदार्फाश, 4 आरोपी गिरफ्तार

वेब वार्ता, देवरिया

देवरिया जिले में म्यूल बैंक खातों व क्रिप्टो ट्रेडिंग एप के जरिए साइबर फ्रॉड की रकम को खपाकर अवैध कमाई करने वाले गिरोह का गौरीबाजार पुलिस ने पदार्फाश किया है। गिरोह में 24 लोग शामिल थे। पुलिस ने इनमें चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के पास से दो पाइनलैब फोन-पे पीओएस मशीन, अलग-अलग नाम से बने एक ही नंबर के तीन आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड व 52 हजार रुपये नकद समेत अन्य सामान बरामद हुआ है।

शहर के साकेतनगर का रहने वाला पवन वर्मा पुत्र पप्पू वर्मा ने गौरीबाजार पुलिस को तहरीर देकर इसराफिल पुत्र कलामुद्दीन व अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की जांच के दौरान यह पता चला कि मुकदमा दर्ज कराने वाला पवन वर्मा व तीन अन्य लोग मिलकर बाइनेंस, टीजी एक्सचेंज व आइपे एप के माध्यम से अन्य लोगों का म्यूल बैंक खाता, आधार कार्ड, पैन व सिमकार्ड का प्रयोग कर अकाउंट निर्मित करते हैं। इसके बाद उस अकाउंट में क्रेडिट व कैश के आधार पर डिजिटल करेंसी की खरीद-फरोख्त कर अवैध धन अर्जित करते हैं। इस फजीर्वाड़े में इनके अलावा इसराफिल, निखिल मणि त्रिपाठी, विशाल, शुभम मणि, रोशन वर्मा, वारिस वर्मा, असलान उर्फ इरफान समेत उसके अन्य साथी भी शामिल हैं।

डिजिटल करेंसी को भारतीय रुपये में परिवर्तित कर उस धनराशि को म्यूल खाते से निकासी करने के लिए म्यूल खाता ओसामा, इरशाद व सैफ उपलब्ध कराते थे। वहीं अन्य लोग प्राप्त होने वाले अवैध धनराशि से डिजिटल करेंसी की खरीद-फरोख्त करते थे, जिसमें इसराफिल भी इनका सहयोगी था।

पुलिस ने आरोपित शुभम सिंह के घर से दो सिम कार्ड सिम बाउल, दो पाइनलैब फोन-पे पीओएस मशीन, एक ही नंबर के अलग-अलग नाम से तीन आधार कार्ड, एक इंडियन बैंक की मुहर, एक पैन कार्ड, एक निर्वाचन कार्ड, दो एटीएम कार्ड, चार पीएनबी एटीएम कार्ड व 52 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं।

इस संबंध में गौरव कुमार सिंह, सीओ सलेमपुर, प्रभारी साइबर सेल ने बताया कि एक दर्ज मुकदमे की जांच में पता चला कि पवन व उसके सहयोगी साइबर फ्राड का पैसा म्यूल अकाउंट में मंगाते हैं और उसी साइबर फ्राड के पैसे से डिजिटल करेंसी की खरीद-फरोख्त कर अवैध धन अर्जित करते हैं। इस संबंध में 24 आरोपितों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। इनमें चार आरोपितों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।

रकम को डिजिटल करेंसी के जरिए खपाने का खुलासा

पुलिस की मानें तो इसमें रोशन वर्मा व वारिस वर्मा की ओर से अवैध डिजिटल करेंसी व साइबर फ्रॉड के धन को जालसाजी से लॉड्रिंग, लेयरिंग व कैश आउट करने के लिए किया जा रहा था। जबकि विशाल मिश्र, शुभम मणि त्रिपाठी व अभिषेक की ओर से नगदी रुपयों को लेकर डिजिटल करेंसी अपने वालेट से इनके वालेट में भेजने का काम किया जा रहा था।

क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 24 पर केस

मामले में पुलिस ने 24 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। वहीं गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने जिन चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है, उनमें पवन वर्मा पुत्र पप्पू वर्मा निवासी साकेतनगर सदर कोतवाली, शुभम सिंह पुत्र इंद्रजीत सिंह कांशीराम आवास साकेत नगर, सैफ अंसारी पुत्र हफीज अंसारी निवासी लाहिलपार थाना बरियारपुर व रोशन वर्मा पुत्र विन्ध्याचल प्रसाद वर्मा निवासी आदर्श नगर शामिल हैं।

कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एअर पोर्ट से नियमित उडान के लिए

वेब वार्ता, कुशीनगर

कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से नियमित उड़ान के लिए आइएलएस (इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम) की बाधा अभी दो माह और बनी रहेगी, ऐसा स्वयं एयरपोर्ट अथारिटी कह रहा। यही वजह है कि, एयरपोर्ट अथारिटी और विमानन कंपनियों के मध्य कई दौर की वार्ता और स्थलीय निरीक्षण के बाद भी उड़ान के लिए आइएलएस के बिना कोई भी कंपनी राजी नही हो रही।

उड़ान के लिए पूरी तरह फिट बताने वाला विभाग अब कह रहा है कि, वर्ष 2022 से चल रहे आइएलएस के लगाने व इंस्टालेशन के प्रक्रिया में दो माह और लगेंगे। ऐसे में विंटर शिड्यूल में भी उड़ान की संभावना पर ग्रहण लग गया है। देश के विभिन्न शहरों से आटो पायलट मोड में उड़ान भर रही विमानन कंपनियां जीपीएस मोड के सहारे नियमित उड़ान भरने को राजी नही हो रही हैं। ऐसे में आइएलएस के के चालू प होने से 400 करोड़ की लागत से बना एयरपोर्ट बेमतलब बना हुआ है।

आइएलएस के लिए दस जून 2022 को रूस की कंपनी साइंटफिक एंड प्रोडक्शन कारपोरेशन-रेडियो टेक्निकल सिस्टम व एयरपोर्ट अथारिटी के मध्य अनुबंध हुआ था। 2024 में आयातित 3.8 करोड़ मूल्य का आइएलएस एनपीओ आरटीएस 734 माडल का यह सिस्टम कैट वन श्रेणी का है।

बता दें कि, अथारिटी के समर शिड्यूल में उड़ान को लेकर कई दौर के वार्ता के बाद भी आइएलएस विहीन एयरपोर्ट से विमानन कंपनियां तैयार नहीं हुईं। इस बीच शासन व प्रशासन स्तर से उड़ान के दावे जरूर किए जाते रहे। इस संबंध में प्राणेश राय, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट निदेशक ने बताया कि दो माह में आइएलएस इंस्टाल हो जाएगा। परीक्षण पश्चात एयरपोर्ट केवल कंपनियों की ही नहीं, उड़ान की सभी अंतरराष्ट्रीय शर्तें पूरी कर लेगा। उसके बाद उड़ान का रास्ता साफ हो जाएगा।

रंजिश में हजारों यूकेलिप्टिस के पेड़ तोड़ने का आरोप, पांच लाख का नुकसान

वेबवार्ता/हरदोई। बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के अटिया शाहपुर गांव में रंजिश को लेकर खेत में तैयार की गई यूकेलिप्टिस की नर्सरी को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया है। गांव निवासी एक युवक ने सात लोगों पर रात के अंधेरे में नर्सरी में लगे हजारों यूकेलिप्टिस के पेड़ तोड़कर नष्ट करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने बेनीगंज कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। अटिया शाहपुर निवासी बेढब पुत्र छोटकउनु रैदास ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसने अपने खेत में यूकेलिप्टिस के हजारों पौधे तैयार किए थे। आरोप है कि छह अगस्त की रात गांव के ही रामू, श्यामू, नान्हे और पुत्ती पुत्रगण बेनी, राहुल व मुकेश पुत्रगण बूधई तथा पराना पत्नी प्रशादी ने रंजिश के चलते उसकी नर्सरी में लगे छोटे-छोटे पेड़ों को तोड़कर नष्ट कर दिया। पीड़ित के अनुसार शुक्रवार सुबह जब वह खेत पर पहुंचा तो नर्सरी की हालत देखकर उसके होश उड़ गए। बड़ी संख्या में पेड़ टूटे और जमीन पर बिखरे पड़े थे। बेढब ने बताया कि पेड़ों को नष्ट किए जाने से उसे करीब पांच लाख रुपये का नुकसान हुआ है। घटना के बाद उसने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी और मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई।

कुशीनगर में नारायणी नदी का कहर, बांध और गांवों पर मंडराया बाढ़ का खतरा

नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही वर्षा के बीच नारायणी नदी(बड़ी गंडक नदी) का बढ़ा डिस्चार्ज अब तटबंधों और ठोकरों खतरा खड़ा करने लगा है।

वेब वार्ता, कुशीनगर

खड्डा तहसील के मदनपुर सुकरौली के समीप स्थित ठोकर नंबर-दो पर नदी के तेज बहाव के कारण सुरक्षा ब्लाक धंसने शुरू हो गए हैं।

सूचना मिलते ही बाढ़ खंड विभाग के अधिकारियों में हलचल मच गई। एसडीओ मनोरंजन कुमार टीम के साथ पहुंचे। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को मरम्मत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

एसडीओ ने बताया कि नदी के बढ़ते दबाव के कारण कुछ सुरक्षा ब्लाक धंसे हैं। प्रभावित स्थल पर तत्काल मरम्मत कार्य शुरू करा दिया गया है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। नदी के बहाव के अनुसार आवश्यक सुरक्षात्मक कार्य कराए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ चिंता बढ़ गई है।

रोहुआ नाला उफनाया, दियारा का संपर्क टूटा, नाव बनी सहारा

नारायणी नदी के बढ़े जलस्तर का असर अब दियारा क्षेत्र के आवागमन पर भी पड़ने लगा है। बिहार के नौरंगिया होकर दियारा क्षेत्र को जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित रोहुआ नाला उफान पर होने से सड़क संपर्क पूरी तरह बाधित हो गया है। इसके चलते ग्रामीणों को आवागमन के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। नाला पार करने के बाद बड़े पेड़ के गिर जाने से आवागमन बाधित भी हो गया है।

विभाग से ठोकर की मजबूती सुनिश्चित करने और कटान रोकने को प्रभावी कदम उठाने की मांग की है।दूसरी ओर नारायणी के डिस्चार्ज में पांच दिनों से लगातार वृद्धि हो रही है। रविवार को 1.09 लाख क्यूसेक से शुरू हुआ डिस्चार्ज सोमवार को 1.15 लाख, मंगलवार को 1.29 लाख और बुधवार को बढ़ते हुए 1.58 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया। गुरुवार को भी इसमें और वृद्धि दर्ज की गई तथा डिस्चार्ज 1.69 लाख क्यूसेक हो गया।

पिपराघाट गेज पर नदी का जलस्तर 74.55 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान 76.20 मीटर से 1.65 मीटर नीचे है। एपी बांध के जवही दयाल के पास नारायणी नदी अप साइड से तटबंध के बिल्कुल निकट बह रही है। नोनिया पट्टी, कचहरी टोला और डीह टोला के समीप भी नदी का दबाव बना हुआ है। बीच धारा में कई स्थानों पर तेज ब्लैक रोलिंग होने से कटान की आशंका बढ़ गई है।

पूरा कर लिया जायेगा

ग्रामीणों का कहना है कि, यदि डिस्चार्ज में और वृद्धि हुई तो बांध के जर्जर हिस्सों पर दबाव बढ़ सकता है। एसडीओ बाढ़ खंढ तमकुही दीपरतन सिंह ने बताया कि, बांध पर दबाव नहीं है। जल्द ही अधूरे कार्य को पूरा करा लिया जाएगा।

उठानी पड़ रही है परेशानी

रोहुआ नाला में पानी बढ़ने से दियारा क्षेत्र के शिवपुर, हरिहरपुर, नरायनपुर, मरिचहवा, बसंतपुर समेत आसपास के गांवों का संपर्क प्रभावित हो गया है। रोजमर्रा के कार्य, खेती-किसानी और आवश्यक सामान की आवाजाही में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों और बीमार लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है।

जिला प्रशासन ने किया जिला कारागार का निरीक्षण

देवरिया 08 अगस्त। देवरिया जिले में जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी एवं पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने जिला कारागार का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने महिला बैरक के निरीक्षण के दौरान महिला बंदियों के साथ रह रहे बच्चों के लिए पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने तथा उनके नियमित टीकाकरण सहित बच्चों से संबंधित अन्य आवश्यक गतिविधियों एवं सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

महत्वपूर्ण ख़बर

वॉट्सएप भारत में उम्र सत्यापन का परीक्षण कर रहा है, नए डेटा कानून का अनुपालन लक्ष्य

■ नई दिल्ली। भारत में करोड़ों वॉट्सएप यूजर्स के लिए अहम खबर है। मेटा के स्वामित्व वाले लोकप्रिय मैसेजिंग एप ने देश में उम्र सत्यापन फीचर का एक शुरूआती पायलट टेस्ट शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में लागू होने वाले नए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीएपी) एक्ट का अनुपालन सुनिश्चित करना है। आसान भाषा में कहे तब वॉट्सएप कानूनी दायरे में रहते हुए यूजर्स की उम्र की सही और सुरक्षित जानकारी हासिल करने के तरीकों पर काम कर रहा है।

यह कदम विशेष रूप से नए कानून के उन प्रावधानों के तहत उठाया जा रहा है, जो नाबालिगों के डेटा और उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल को लेकर सख्त नियम तय करते हैं। वर्तमान में, यह परीक्षण अभी केवल चुनिंदा यूजर्स के एक छोटे और सीमित समूह पर आजमाया जा रहा है।

ईरान की अमेरिका को दो टूक कहा- न झुकेंगे न रुकेंगे

■ तेहरान। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने अमेरिका और इजरायल को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि ईरान के आत्मसमर्पण की उम्मीद करना सिर्फ एक सपना है। उन्होंने कहा कि ईरान ने युद्ध की शुरूआत नहीं की और जिसने इसे शुरू किया है, वही इसे खत्म करेगा। पेजेशकियान ने दावा किया कि सैन्य दबाव के जरिए ईरान को कमजोर करने की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं और देश मुश्किल हालात के बावजूद मजबूती से खड़ा है। शुक्रवार को ईरानी सरकारी टेलीविजन को दिए इंटरव्यू में पेजेशकियान ने कहा कि युद्ध शुरू होने से पहले ईरानी सरकार बातचीत के जरिए विवाद का समाधान निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन परिस्थितियां धीरे-धीरे सैन्य टकराव की ओर बढ़ गईं।

दिल्ली-एनसीआर में जलभराव से जाम, बिहार में 300 घर डूबे, हिमाचल में 162 सड़कें बंद, यूपी में नदियां उफान पर

बारिश-लैंडस्लाइड के चलते अमरनाथ यात्रा जम्मू में रोकी

नई दिल्ली। देश के कई राज्यों में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। जम्मू-कश्मीर में बारिश और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए शनिवार को जम्मू से अमरनाथ यात्रा रोक दी गई। वहीं दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार को हुई तेज बारिश के बाद कई प्रमुख सड़कों पर जलभराव हो गया।

दिल्ली-गुरुग्राम हाईवे समेत कई स्थानों पर करीब चार फीट तक पानी भरने से वाहन फंस गए और लंबा ट्रैफिक जाम लगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में भी बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़ रहे हैं।

खराब मौसम और अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए शनिवार को भगवती नगर बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का नया जत्था कश्मीर के लिए रवाना नहीं किया गया। प्रशासन जम्मू-श्रीनगर हाईवे की स्थिति और मौसम पर लगातार नजर रख रहा है। मौसम विभाग ने जम्मू क्षेत्र में 11 अगस्त तक कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश के साथ अचानक बाढ़ और भूस्खलन की आशंका जताई है।

अब तक 4.75 लाख से अधिक श्रद्धालु अमरनाथ गुफा के दर्शन कर चुके हैं। शनिवार सुबह हल्की से मध्यम बारिश के बावजूद जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर यातायात सामान्य बताया गया।

दिल्ली में 2011 के बाद सबसे ज्यादा बारिश

दिल्ली में शुक्रवार को हुई तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। प्रमुख सड़कों पर पानी भरने के कारण वाहन बीच रास्ते में फंस गए और यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। मौसम विभाग ने शनिवार को भी दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगस्त के पहले सप्ताह में दिल्ली में अब तक 127 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जो 2011 के बाद इस अवधि में सबसे अधिक बताई जा रही है।

बिहार में गंडक का पानी 300 घरों में घुसा

नेपाल में हो रही तेज बारिश के कारण बिहार में नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी उफान पर है, जबकि बगहा में गंडक नदी का पानी करीब 300 घरों में घुस गया है। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। नेपाल की बारिश और नदियों में बढ़ते जल स्तर के कारण बिहार के मुजफ्फरपुर में जनजीवन प्रभावित हुआ है।

हिमाचल में 162 सड़कें बंद

हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के कारण ब्यास नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। चंडीगढ़-मनाली और मंडी-पठानकोट हाईवे समेत राज्य की 162 सड़कें बंद हो गई हैं। वहीं राजस्थान के 30 जिलों में तेज बारिश का यलो अलर्ट है। सीकर और झुंझुनूं में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, जबकि भरतपुर में स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है।

यूपी में नदियां उफान पर, घाट डूबे

उत्तर प्रदेश में करीब 25 दिनों से जारी बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाट डूब गए हैं और 84 घाटों का संपर्क टूट गया है। कई छोटे मंदिरों में भी पानी घुस गया है। फरुर्खाबाद में गंगा के कटान से पिछले दो दिनों में आठ घर नदी में समा गए, जबकि 10 से अधिक गांवों का संपर्क प्रभावित हुआ है। बलिया में सरयू नदी में 27 घर समा चुके हैं। आगरा में सड़क धंसने से करीब 20 फीट गहरा गड्ढा बन गया।

हिमाचल के चंबा में निजी बस खाई में गिरी, 7 की मौत, 11 घायल

शिमला। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में शनिवार सुबह एक निजी बस हादसे में सात लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हुए हैं। दुर्घटना चुराह विधानसभा क्षेत्र के तीसा थाना अंतर्गत बैरागढ़ के पास चालूंज मोड़ पर हुई। घायलों में छह की हालत को देखते हुए उन्हें चंबा के पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रेफर किया गया है। मृतकों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के मुताबिक हादसा सुबह करीब 7:15 बजे हुआ। निजी बस बैरागढ़ से चंबा की ओर जा रही थी। चालूंज मोड़ के पास बस अनियंत्रित होकर सड़क से पलटते हुए दूसरी सड़क पर जा पहुंची। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके के लिए रवाना हुईं और राहत-बचाव अभियान शुरू किया गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक दुर्घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस टीम घटनास्थल पर जांच कर रही है और हादसे की परिस्थितियों की जानकारी जुटाई जा रही है। मृतकों की पहचान के साथ दुर्घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है।

मृतकों की पहचान और हादसों के मूल कारणों की जांच शुरू

हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य में पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन विभाग, राजस्व विभाग और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें शामिल हैं। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। प्रशासन की ओर से घटनास्थल से मिल रही जानकारी के आधार पर मृतकों और घायलों से संबंधित विवरण जुटाया जा रहा है। यह हादसा ऐसे समय हुआ है जब हिमाचल प्रदेश में मॉनसून सक्रिय है और कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 13 अगस्त तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। पिछले करीब दो सप्ताह में हिमाचल प्रदेश में यह दूसरा बड़ा सड़क हादसा है। इससे पहले 24 जुलाई को लाहौल-स्पीति के उदयपुर क्षेत्र में पहाड़ी से भारी चट्टान गिरने के बाद एक टाटा सूमो इसकी चपेट में आ गई थी। हादसे में 13 लोगों की मौत हुई थी। चंबा बस हादसे में सात और मौतों के बाद इस मॉनसून सीजन में सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों की संख्या 85 हो गई है। वहीं, बारिश से जुड़े विभिन्न हादसों में अब तक करीब 150 लोगों की मौत हो चुकी है।

शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की कोई भूमिका नहीं

बांग्लादेश की आपत्ति पर नई दिल्ली का दो टूक जवाब

नई दिल्ली। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत में आयोजित वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बांग्लादेश की आपत्ति के बाद भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। साथ ही, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख हसीना की ओर से बांग्लादेश की मौजूदा सरकार को लेकर की गई टिप्पणियों से भारत ने खुद को अलग कर लिया है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि भारत किसी भी ऐसे मंच पर व्यक्त किए गए विचारों का समर्थन नहीं करता। उन्होंने विशेष रूप से उन टिप्पणियों से दूरी बनाई, जो बांग्लादेश की मौजूदा सरकार के संबंध में की गई थीं। जायसवाल ने कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने और द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

दरअसल, शेख हसीना की वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत में आयोजित होने के बाद बांग्लादेश ने इस पर आपत्ति जताई थी। ढाका की

ओर से इस घटनाक्रम को लेकर चिंता व्यक्त किए जाने के बाद नई दिल्ली ने यह स्पष्ट किया कि कार्यक्रम से भारत सरकार का कोई संबंध नहीं था। भारत के इस रुख को दोनों देशों के बीच संवेदनशील संबंधों के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

विदेश मंत्रालय के बयान से यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि भारत बांग्लादेश के आंतरिक राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने को प्राथमिकता देता है।

नेहा बोरा पर स्याही फेंकने की घटना से उठा सुरक्षा पर सवाल

नई दिल्ली। आइसा की अध्यक्ष नेहा बोरा ने खुद पर स्याही फेंके जाने की घटना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद एक व्यक्ति महिला प्रदर्शनकारियों तक कैसे पहुंच गया, इसकी जांच होनी चाहिए। बोरा ने झारखंड सरकार से छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार कर उन्हें स्वीकार करने की अपील भी की। घटना को लेकर बोरा ने प्रशासन से जवाबदेही तय करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के आसपास पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात थे, इसके बावजूद संदिग्ध व्यक्ति महिलाओं के बीच पहुंच गया और स्याही फेंककर निकल गया। उन्होंने पूरे घटनाक्रम की आधिकारिक जांच और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बोरा के मुताबिक, स्याही फेंकने वाले व्यक्ति की पहचान अमरनाथ पांडे के रूप में हुई है। उन्होंने दावा किया कि वह 26 वर्षीय हजारीबाग निवासी और आरएसएस से जुड़ा व्यक्ति है। बोरा ने कहा कि पुलिस और प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए कि सुरक्षा घेरे के बावजूद वह प्रदर्शन स्थल के उस हिस्से तक कैसे पहुंचा, जहां महिला प्रदर्शनकारी मौजूद थीं।

जेन-जी को किसी प्रमाणपत्र की जरुरत नहीं

प्रियंका गांधी ने मोहन भागवत की टिप्पणी पर किया पलटवार

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव एवं वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत की जेन-जी को लेकर की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नई पीढ़ी को उनसे किसी प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, जेन-जी को मोहन भागवत जी से किसी प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं है।

कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी की यह प्रतिक्रिया मोहन भागवत के उस बयान के बाद आई है, जिसमें

उन्होंने जेन-जी और जेन-अल्फा की तारीफ करते हुए उन्हें गंभीर

संघ प्रमुख ने कहा था- देश के प्रति गंभीर दृष्टिकोण रखते हैं आज के युवा

दृष्टिकोण वाला बताया था और उन्हें साधने की कोशिश की थी। दरअसल प्रियंका गांधी से संसद परिसर में पत्रकारों ने भागवत की टिप्पणी से जुड़ा सवाल किया था, जिस पर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, ह्यजेन-जी को मोहन भागवत जी से किसी प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है।ह्न इससे पहले मुंबई के एक कार्यक्रम में भागवत ने कहा था कि लोकतंत्र में विरोध-प्रदर्शन को संवाद का एक वैध और आवश्यक माध्यम है। उन्होंने जेन-जी और जेन-अल्फा पीढ़ी को साधते हुए कहा था, कि आज के युवा सवाल पूछते हैं, जवाब चाहते हैं और समाज व देश के प्रति गंभीर दृष्टिकोण रखते हैं। उनके अनुसार, नई पीढ़ी को समझने और उनकी बात सुनने की आवश्यकता है। इस पर प्रियंका गांधी ने बहुत ही कम शब्दों में जोरदार तरीके से पलटवार किया है, जिसका प्रभाव आगे राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के तौर पर देखने को मिल सकता है।

महुआ मोइत्रा की वर्चुअल पेशी की मांग खारिज, जज की टिप्पणी पर विवाद

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 7 अगस्त को तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने एक आपराधिक मामले की जांच के सिलसिले में पुलिस के सामने वर्चुअली पेश होने की अनुमति मांगी थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता की टिप्पणी को लेकर राजनीतिक और सोशल मीडिया हलकों में विवाद शुरू हो गया है। दरअसल, महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक फेसबुक पोस्ट को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने उन्हें 14 अगस्त को जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं मोइत्रा की ओर से वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने दलील दी कि सांसद को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ में शामिल होने की अनुमति दी जाए।

वकील ने अदालत को बताया कि पिछली बार जब मोइत्रा अपने निर्वाचन क्षेत्र के पुलिस स्टेशन गई थीं, तब उन पर अंडे फेंके गए थे। ऐसे में दोबारा पुलिस स्टेशन जाने पर भीड़ द्वारा उन्हें निशाना बनाए जाने का खतरा है। हालांकि, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने वर्चुअल पेशी की मांग पर राहत देने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस दत्ता ने टिप्पणी की कि राजनीति में आने के बाद मोइत्रा को अंडों से क्यों डर लगता है, जबकि स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने सीने पर गोलियां खाई थीं। अदालत के इस रुख के बाद मोइत्रा के वकील ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसके बाद अदालत ने इसे खारिज कर दिया।

अदालत की टिप्पणी के बाद राजनीतिक हलकों में भी प्रतिक्रिया सामने आई। एक राजनीतिक संगठन के प्रवक्ता सौरव दास ने न्यायिक जवाबदेही की जरूरत बताते हुए टिप्पणी को निंदनीय बताया। संगठन के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी कहा कि संवैधानिक अदालतों से विपक्षी नेताओं के प्रति इस तरह की टिप्पणियों की अपेक्षा नहीं की जाती। इस बीच, कलकत्ता हाई कोर्ट ने 21 जुलाई को कथित नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में मोइत्रा को 5 अक्टूबर तक दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम राहत दी थी। मोइत्रा इन मामलों को मनगढ़ंत आरोपों पर आधारित बताती रही हैं।

भारत-इजरायल के ह्यडिफेंस पैक्ट की खबर फर्जी

नई दिल्ली। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये के बीच हालिया रणनीतिक रक्षा समझौते के बाद सोशल मीडिया पर भारत और इजरायल के बीच नए रक्षा समझौते की पहल को लेकर दावा वायरल हो गया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस दावे को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे फर्जी खबर बताया है। मंत्रालय ने लोगों से सोशल मीडिया पर प्रसारित ऐसे भ्रामक और दुर्भावनापूर्ण कंटेंट से सावधान रहने की अपील की है।ह्न वायरल दावे की शुरूआत तुर्किये के एक मीडिया आउटलेट की रिपोर्ट से हुई थी।

शेख हसीना फिर क्यों हुई एक्टिव, बांग्लादेश जाने की बात दोहराई

नई दिल्ली। 5 अगस्त 2024 भयंकर विरोध और हिंसा के बीच शेख हसीना बांग्लादेश से भारत आ गई थीं। ठीक दो साल बाद शुक्रवोर को दिल्ली में हसीना ने पहली बार वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मैं दिसंबर में बांग्लादेश जाऊंगी।

आखिर हसीना का आगे का प्लान क्या है और क्या भारत इसमें उनके साथ है, इसका भारत-बांग्लादेश रिश्तों पर क्या असर होगा? दो साल से भारत में अज्ञात जगह पर रह रहीं शेख हसीना बीते करीब दो महीने से दोबारा सक्रिय हुईं और वापस बांग्लादेश जाने की बात कर रही हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 29 जून 2026 को हसीना ने एक ई-मेल के जरिए कहा था कि मुझे मौत का डर नहीं है। मैंने 1975 में अपना पूरा परिवार खो दिया था। हर साजिश से लड़ते हुए बांग्लादेश की अवाम के साथ खड़ी रही और पांच बार बांग्लादेश की पीएम चुनी गई। मेरी जिंदगी बांग्लादेश की जनता, अवामी लीग और बांग्लादेश के हित से जुड़ी रही है। मैं हर रुकावट और साजिश को पार करके इस साल अपने मुल्क वापस जाऊंगी। इंटरव्यू में शेख हसीना ने मौजूदा पीएम

तारिक रहमान की सरकार पर कई आरोप लगाते हुए कहा कि बांग्लादेश में भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ रही है। सरकार पूरी तरह नाकाम है।

बता दें 10 जुलाई की सुबह शेख हसीना ने एक इंटरव्यू में कहा कि दिसंबर 2026 तक वो बांग्लादेश लौटेंगी और अपनी पार्टी के कुछ और निर्वासित नेताओं के साथ सरेंडर करेंगी, भले ही उन्हें मार दिया जाए। बता दें 5 अगस्त को शेख हसीना दिल्ली में फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया के एक कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुईं। उन्होंने अपना कैमरा ऑन नहीं किया, यानी वो सामने नहीं आईं। हसीना ने कहा कि मुझे यह पता नहीं था कि मैं देश छोड़कर जा रही थी। मैं तो अपने पैतृक गांव तुंगीपाड़ा जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन हालात ऐसे बने कि देश छोड़ना पड़ा। मुझे पता है कि वे मुझे जेल में डाल सकते हैं, मार भी सकते हैं, फिर भी मैं बांग्लादेश जाऊंगी। लोगों का समर्थन मेरे लिए बहुत जरूरी है। मौत की सजा, झूठे मुकदमे और दिखावटी सुनवाई से मुझे डरा नहीं सकते।

बांग्लादेश लौटे बिना मुमकिन नहीं है

उन्होंने कहा कि भारत हमेशा बांग्लादेश का अच्छा दोस्त रहा है। जब भी बांग्लादेश किसी मुश्किल हालात में होता है, भारत उसके साथ खड़ा रहता है। सरकारों के बीच के रिश्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत हमेशा से एक अच्छा दोस्त रहा है और आगे भी रहेगा। ऐसा माना जा रहा है कि शायद शेख हसीना को लगने लगा है कि दोबारा बांग्लादेश में ताकत से खड़े होने का मौका है और सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जा सकता है।ह्न इसके कुछ संकेत भी दिखने लगे है। प्रतिबंध के बावजूद अवामी लीग दोबारा सक्रिय हो रही है। 23 जून को पार्टी ने 77वां स्थापना दिवस मनाया था। दर्जनों कार्यकताओं ने गिरफ्तारी भी दी थी। इसके अलावा अमेरिका में रह रहे हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय बांग्लादेश के मुद्दों पर एक्टिव हैं। अगर हसीना उनके लिए राजनीतिक जमीन तैयार करना चाहें, तो भी ये बिना बांग्लादेश लौटे मुमकिन नहीं है।

शांति और लंबित मुद्दों के समाधान की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं भारत-चीन

दोनों देशों के बीच हुई सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वय तंत्र की 36वीं बैठक

नई दिल्ली। भारत और चीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद के बावजूद रिश्तों में धीरे-धीरे सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगे हैं। नई दिल्ली में आयोजित भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वय तंत्र की 36वीं बैठक ने साफ संकेत दिया है कि दोनों देश बातचीत के जरिए सीमा पर शांति बनाए रखने और लंबित मुद्दों के समाधान की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं।

हालांकि भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया कि द्विपक्षीय संबंधों में वास्तविक प्रगति तभी संभव है, जब एलएसी पर पूरी तरह शांति और स्थिरता बनी रहे। यही वजह है कि सीमा प्रबंधन, सैन्य समन्वय, सीमा निर्धारण, ट्रांस-बॉर्डर नदियों और पारंपरिक व्यापार जैसे सभी अहम मुद्दों पर भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ मजबूती से रखा। बता दें नई दिल्ली में आयोजित बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया, जबकि चीनी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा एवं समुद्री मामलों की महानिदेशक होउ यानची ने किया।

रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों ने एलएसी की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करते हुए इस बात पर सहमति जताई कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता ही द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास की सबसे अहम आधारशिला है। दोनों पक्षों ने यह भी तय किया कि किसी भी गलतफहमी या सैन्य गलत आकलन से बचने के लिए राजनयिक और सैन्य स्तर पर स्थापित सभी संवाद तंत्रों का निरंतर इस्तेमाल

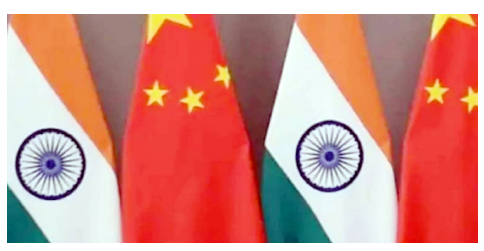

किया जाएगा। स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकों और डब्ल्यूएमसीसी जैसे मंचों को आगे भी सक्रिय बनाए रखने पर सहमति बनी।

यह बैठक ऐसे समय हुई है जब दोनों देशों के बीच सीमा पर व्यावहारिक सहयोग भी धीरे-धीरे बहाल हो रहा है। छह सालों के अंतराल के बाद उत्तराखंड के लिपुलेख और हिमाचल प्रदेश के शिपकी ला दर्रे से पारंपरिक सीमा व्यापार दोबारा शुरू होना इसी दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। चीन ने शुरूआती चरण में सीमित संख्या में व्यापारियों को अनुमति दी है, लेकिन यह पहल दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली की प्रक्रिया का प्रतीक मानी जा रही है। इससे पहले दोनों देश नाथू ला समेत तीन अधिकृत व्यापारिक मार्गों को चरणबद्ध तरीके से खोलने पर भी सहमत हो चुके हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक विदेश सचिव विक्रम मिसरी की हालिया चीन यात्रा ने भी इस कूटनीतिक प्रक्रिया को नई गति दी। बीजिंग में उन्होंने चीन के वरिष्ठ नेताओं के साथ व्यापक वार्ता कर पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी चिनफिंग की उस साझा सोच को आगे बढ़ाने पर चर्चा की, जिसके मुताबिक भारत और चीन प्रतिस्पर्धी होने के साथ-साथ विकास के अवसरों में साझेदार भी बन सकते हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले साल पीएम मोदी भी एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन गए थे, जहां दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय संवाद को आगे बढ़ाने की दिशा में अहम चर्चा हुई थी। सामरिक दृष्टि से देखें तो भारत की नीति अब पहले से कहीं ज्यादा संतुलित और परिपक्व दिखाई देती है। एक ओर भारत सीमा पर सैन्य तैयारियों, आधारभूत ढांचे और निगरानी क्षमता को लगातार मजबूत कर रहा है, वहीं दूसरी ओर वह संवाद के सभी वैध माध्यम खुले रखकर यह संदेश भी दे रहा है कि शांति उसकी प्राथमिकता है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता स्वीकार नहीं होगा।

ताजा खबर
संक्षिप्त

30 दिवसीय अखण्ड रामचरित मानस पाठ का आयोजन

रायपुर। बुढ़ापारा ,सप्रे शाला स्थित श्री हनुमान मंदिर में 30 दिवसीय अखण्ड रामायण पाठ का आयोजन पंडित श्री दिलीप शर्मा जी के मार्ग दर्शन में किया जा रहा है. विदित हो की इस पाठ का आयोजन विगत 25 वर्षों से प्रत्येक श्रावण मास में किया जाता है. 29 जुलाई (गुरु पूर्णिमा) से प्रारंभ अखंड रामायण पाठ का समापन 28 अगस्त (रक्षा बंधन)को 24 घंटे की भव्य राम चरित मानस पाठ के दोहे, छंद एवं सोरठे के साथ ? राम रामायण नम" के 24 घंटे अनवरत उच्चारण के साथ यज्ञ आहुति के पश्चात सम्पन्न होगा .उपरोक्त जानकारी समिति के अध्यक्ष मनोज इनचुरकर ने दी.

धमतरी में खुलेगा राज्य का पहला पशु औषधि केंद्र, सस्ते दरों पर मिलेंगी दवाएं

धमतरी. धमतरी जिले के पशुपालकों के लिए राहत भरी खबर है. पशुओं के इलाज के लिए अब जेनेरिक दवाइयां सस्ती और उचित दरों पर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगी. धमतरी विकासखंड में जिले के प्रथम पशु औषधि विक्रय केंद्र यानी PAVK की स्थापना की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है. पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित Livestock Health and Disease Control Programme यानी LHDCP के तहत पशुपालकों को गुणवत्तापूर्ण और किफायती पशु औषधियां उपलब्ध कराने की पहल की जा रही है. इसी क्रम में धमतरी विकासखंड में प्रस्तावित प्रथम पशु औषधि विक्रय केंद्र के लिए प्राप्त आवेदन पोर्टल पर स्वीकृत होने के बाद आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन 6 अगस्त 2026 को पूरा कर लिया गया. खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ में पोर्टल पर स्वीकृत आवेदनों में दस्तावेज सत्यापन के चरण तक पहुंचने वाला यह अब तक का एकमात्र आवेदन बताया गया है. ऐसे में इस पहल को लेकर धमतरी जिले को अग्रणी अवसर मिला है. ोंद्रय का संचालन शुरू होने के बाद धमतरी विकासखंड क्षेत्र के पशुपालकों को जेनेरिक पशु औषधियां स्थानीय स्तर पर सस्ती दरों में उपलब्ध हो सकेंगी. इससे पशुओं के इलाज में होने वाला खर्च कम होने के साथ समय पर दवाइयां मिलने में भी मदद मिलेगी. कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री पशुधन को राज्य की संपदा मानते हैं और उनका निर्देश है कि पशुपालकों को बेहतर और सुलभ पशु चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं. राज्य की साय सरकार की सोच है कि पशुधन ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की आय का महत्वपूर्ण आधार है. ऐसे में पशुओं के लिए दवाइयों की आसान और किफायती उपलब्धता पशुपालकों की आजीविका को मजबूत करने में मददगार साबित होगी.ोंद्रय के शुरू होने से पशुपालकों को पशु औषधियों के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों में जाने की जरूरत भी कम होगी. यह पहल जिले में पशुधन स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, किफायती और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

सीएम साय ने जारी की महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त

डीबीटी के माध्यम से 630.55 करोड़ रुपए की राशि जारी

रायपुर. छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिये बड़ी खुशखबरी है। प्रदेश के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय ने आज शुक्रवार को महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त जारी कर दी है। प्रदेश की 67 लाख 20 हजार 125 महिलाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से 630.55 करोड़ रुपए की राशि भेज दी गई है। योजना के तहत अब तक कुल 19,444.33 करोड़ की राशि का भुगतान महिलाओं के खातों में हो चुका है। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े मौजूद रहीं इस दौरान

सीएम साय ने कहा कि महिलाओं का सम्मान, सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। महतारी वंदन योजना इस दिशा में बड़ा बदलाव ला रही है।

67.20 लाख महिलाओं को सीधा लाभ

योजना के तहत प्रदेश की 67 लाख 20 हजार 125 महिलाओं को लाभ दिया गया। सभी हितग्राही महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से सीधे राशि भेज दी गई। ताकि पारदर्शिता बनी रहे और लाभ सीधे पात्र महिलाओं को मिल सके।

उन्होंने कहा कि किसी भी समाज और राज्य की प्रगति तब तक नहीं हो सकती, जब तक महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और सामाजिक रूप से मजबूत न किया जाये। ऐसे में यह योजना महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देने के साथ ही उनके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को और ज्यादा मजबूत कर रही है। प्रदेश की माताओं और बहनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है।

630.55 करोड़ की राशि ट्रांसफर

राज्य सरकार ने 30वीं किस्त के तहत कुल 630.55 करोड़ की राशि जारी की है। यह पूरी राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में भेजी गई। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं को घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी खर्चों में सहायता मिलेगी।

19,444.33 करोड़ से अधिक का भुगतान

महतारी वंदन योजना शुरू होने के बाद से अब तक प्रदेश की महिलाओं को कुल 19,444.33 करोड़ की राशि दी जा चुकी है। यह योजना राज्य की सबसे बड़ी महिला कल्याण योजनाओं में शामिल हो चुकी है और लाखों परिवारों को इसका सीधी लाभ मिल रहा है।

छत्तीसगढ़ का हैंडलूम ब्रांड कोशल फैब लॉन्च

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर मुख्यमंत्री साय ने बुनकरों को दी सौगात

रायपुर. छत्तीसगढ़ का कोसा और बस्तर की बुनाई प्रदेश के पारंपरिक हथकरघा उत्पाद देश-दुनिया में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ के हथकरघा उत्पादों को %लोकल टू ग्लोबल% की पहचान दिलाना है। इसके लिए आधुनिक डिजाइन, कौशल उन्नयन, प्रशिक्षण, ब्रांडिंग, बाजार और नए बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। ये बातें छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर शुक्रवार को राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित प्रदेश स्तरीय बुनकर सम्मेलन एवं स्वदेशी प्रदर्शनी में कहीं।

इस दौरान सीएम साय ने छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा संघ के नए प्रीमियम हैंडलूम ब्रांड %कोशल फैब% का शुभारंभ करते हुए उसके लोगो एवं कैटलॉग का विमोचन किया। उन्होंने हथकरघा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम ने रेशम, हथकरघा, हस्तशिल्प, खादी एवं माटीकला बोर्ड के कई हितग्राहियों और मेधावी छात्र-छात्राओं को 10 करोड़ 90 लाख रुपये से अधिक की अनुदान और पुरस्कार राशि बांटी।

सरेंडर महिलाओं ने किया रैंप वॉक

इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी और खास बात ये रही कि बस्तर की आत्मसमर्पित नक्सली महिलाओं ने स्वदेशी फैशन शो में रैंप वॉक किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के पारंपरिक कोसा सिल्क और अन्य हैंडलूम परिधानों का प्रदर्शन किया। यह प्रस्तुति मुख्यधारा से जुड़कर आत्मनिर्भर जीवन की ओर बढ़ती महिलाओं के आत्मविश्वास, सम्मानजनक पुनर्वास और बदलते बस्तर की सकारात्मक तस्वीर की सशक्त अभिव्यक्ति रही। इस दौरान लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आत्मसमर्पित महिलाओं से संवाद भी किया। उनका उत्साह बढ़ाया।

राज्य सरकार ने पूरे किये वादे

सीएम साय ने कहा कि 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के तहत किए गए वादों को राज्य सरकार ने पूरा किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लाखों गरीब परिवारों का पक्के घर का सपना साकार हो रहा है। किसानों को धान खरीदी की अंतर राशि का भुगतान, भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता, महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण और तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका योजना दोबारा शुरू की गई है।

स्वदेशी अपनाने का आह्वान: मंत्री राजेश अग्रवाल

प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने प्रदेशवासियों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और हथकरघा से निर्मित वस्तुओं के उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान का उल्लेख करते हुए कहा कि स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करना केवल आर्थिक गतिविधि नहीं, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक शिल्पकला और लाखों बुनकर परिवारों के सम्मान से जुड़ा जन आंदोलन है। छत्तीसगढ़ के कुशल बुनकरों के निर्मित पारंपरिक गमछा ओढ़कर कहा कि यह गमछा केवल एक परिधान नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान, श्रम, परंपरा और स्थानीय शिल्प कौशल का जीवंत प्रतीक है।

योजना, सांख्यिकी विभाग और आईआईएम के बीच एमओयू

रायपुर। योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राज्य नीति आयोग, छत्तीसगढ़ शासन एवं भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राज्य नीति आयोग की ओर से सचिव भुवनेश यादव एवं आईआईएम रायपुर की ओर से निदेशक-प्रभारी प्रो. संजीव पराशर ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। समझौते के तहत प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, नीति अनुसंधान, परामर्श, डेटा एनालिटिक्स, शोध एवं दस्तावेजीकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा। एमओयू के अंतर्गत शासकीय अधिकारियों के लिए नेतृत्व विकास, मिड-कैरियर एग्जीक्यूटिव एवं कस्टमाइज्ड मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित किए जा सकेंगे। इकोनोमेट्रिक्स, रिसर्च मेथडोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पब्लिक पॉलिसी, नेतृत्व एवं प्रबंधकीय कौशल जैसे क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण दिए जाएंगे। दोनों संस्थान नीति अनुसंधान, प्रभाव आकलन, मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन, बेंचमार्किंग, संस्थागत सुदृढ़ीकरण, रणनीतिक परामर्श और डेटा आधारित निर्णय सहयोग के क्षेत्र में संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। छत्तीसगढ़ की विकास प्राथमिकताओं से जुड़े शोध, केस स्टडी, पॉलिसी ब्रीफ एवं शोध रिपोर्ट भी तैयार की जा सकेंगी।

आईआईएम रायपुर के फैकल्टी एवं विद्यार्थियों द्वारा डेटा एनालिटिक्स आधारित लाइव प्रोजेक्ट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, गवर्नेंस इनोवेशन एवं एप्लाइड रिसर्च किए जा सकेंगे। विद्यार्थियों को समर इंटर्नशिप, फील्ड इमर्शन, लाइव कंसल्टिंग, एक्शन रिसर्च एवं कैपस्टोन प्रोजेक्ट के माध्यम से शासकीय योजनाओं और विकास कार्यक्रमों के साथ व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होगा। एमओयू के तहत संयुक्त कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, पॉलिसी डायलॉग, स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन एवं राउंडटेबल आयोजित किए जाएंगे। आईआईएम रायपुर के विशेषज्ञों, शासकीय अधिकारियों एवं विषय विशेषज्ञों की प्रशिक्षण, शोध एवं परामर्श गतिविधियों में सहभागिता होगी।

छग में नीट-यूजी प्रथम चरण काउंसिलिंग के लिए ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ

रायपुर। कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य भवन, नवा रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय एवं निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित स्नातक पाठ्यक्रम (एमबीबीएस/बीडीएस) में प्रवेश वर्ष 2026 के प्रथम चरण काउंसिलिंग हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये हैं।

सूचना के अनुसार सभी आवेदकों को ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व क्रमांक RULE-503/30/2025/MED, छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) स्नातक प्रवेश नियम, 2025 का, विशेषकर आरक्षण, काउंसिलिंग प्रक्रिया एवं बॉण्ड से संबंधित प्रावधानों का, पूर्णत: अध्ययन करने की सलाह दी गई है।

यह नियमावली वेबसाइट www.cgdme.in एवं https://cgdme.admissions.nic.in/ पर उपलब्ध है। मातृशक्ति के खातों में पहुंची महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त ऑनलाईन आवेदन शुल्क अनारक्षित (R) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (ह्यब्ह्) श्रेणी के आवेदकों के लिए 1000 रुपये, अनुसूचित जनजाति (ST) एवं अनुसूचित जाति (SC) श्रेणी के आवेदकों के लिए 500 रुपये तथा अप्रवासी भारतीय (NRI) श्रेणी के आवेदकों के लिए 10,000 रुपये निर्धारित की गई है, जो अप्रतिदेय (Non Refundable) होगी। पंजीयन राशि (सुरक्षा निधि) संबंधी विवरण के लिए सूचना के पेज क्रमांक 2 पर दी गई तालिका देखने को कहा गया है। ऑनलाईन आवेदन 09 अगस्त 2026 को सुबह 11ः00 बजे से प्रारंभ होकर 16 अगस्त 2026 को रात्रि 11ः59 बजे तक चलेगा। वहीं च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग की प्रक्रिया भी 09 अगस्त 2026 को सुबह 11ः00 बजे से शुरू होकर 17 अगस्त 2026 को रात्रि 11ः59 बजे तक जारी रहेगी। आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा जारी इस सूचना में आवेदकों से अपील की गई है कि ऑनलाईन आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट www.cgdme.in एवं https://cgdme.admissions.nic.in/ का अवलोकन करें।

26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा जीपीएम

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में खेल संस्कृति को नई गति मिल रही है। खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने और उन्हें राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार लगातार प्रभावी पहल कर रही है। इसी कड़ी में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिला 18 से 21 अगस्त तक आयोजित होने वाली 26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। चार दिवसीय इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में प्रदेश के पांचों संभागों से 14 से 19 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 540 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा और खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे। राज्य सरकार खेलों को केवल प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं, बल्कि अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और स्वस्थ जीवन शैली का सशक्त आधार मानती है। शालेय स्तर पर आयोजित होने वाली ऐसी प्रतियोगिताएं युवा खिलाड़ियों की अपनी प्रतिभा निखारने के साथ-साथ बड़े मंचों तक पहुंचने का अवसर प्रदान करती हैं।चार खेलों की स्पर्धाओं से गूंजेगा जीपीएम

प्रतियोगिता के दौरान जिम्नास्टिक (बालक एवं बालिका), क्रिकेट (बालक), ताईक्वांडो (बालक एवं बालिका) तथा कबड्डी (बालिका) की स्पर्धाएं आयोजित होंगी। प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी पांचों संभागों के खिलाड़ी, प्रशिक्षक एवं अधिकारी सहभागिता करेंगे। आयोजन से खिलाड़ियों में प्रतिस्पर्धा की भावना, टीम भावना और खेल उत्कृष्टता को नई दिशा मिलेगा। उत्कृष्ट आयोजन के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार

प्रतियोगिता के सफल एवं गरिमामय आयोजन के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. ने विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक लेकर तैयारियों का विस्तृत जायजा लिया। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ समय-सीमा में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि राज्यभर से आने वाले खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और अधिकारियों को उत्कृष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

बैठक में खेल स्थलों के चयन, खिलाड़ियों के आवास एवं भोजन, परिवहन, स्वास्थ्य परीक्षण, चिकित्सा सुविधा, पेयजल, विद्युत एवं प्रकाश व्यवस्था, साफ-सफाई, सुरक्षा, यातायात प्रबंधन तथा उद्घाटन एवं समापन समारोह की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी विभागों को सौंपे गए दायित्वों का प्रभावी निर्वहन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यह प्रतियोगिता न केवल प्रदेश की उभरती खेल प्रतिभाओं को अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगी, बल्कि गौरेला-पेंड्रा-मरवाही को राज्य के प्रमुख खेल आयोजनों के सफल मेजबान के रूप में नई पहचान भी दिलाएगी।

नक्सल मुक्त क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास में तेजी लाने सहित दिए कई निर्देश

मुख्य सचिव ने ली कैम्पा की समीक्षा बैठक

रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में कैम्पा (CAMPA) की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक मंत्रालय महानदी भवन में आज आयोजित की गई। बैठक में वनों के संरक्षण, पर्यावरण विकास और वनांचल क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए।

मुख्य सचिव ने वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कैम्पा मद के तहत वन क्षेत्रों में पुल-पुलियों, पहुंच मार्गों और आवश्यक भवनों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने विशेष रूप से नक्सल मुक्त हुए क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास के कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया, ताकि इन सुदूर क्षेत्रों तक शासन की पहुंच और विकास का लाभ त्वरित गति से पहुंच सके। बैठक के दौरान

विभाग के अधिकारियों ने अवगत कराया कि वर्ष 2026-27 के लिए 713 करोड़ 73 लाख रुपये की वार्षिक कार्ययोजना को अनुमोदित कर अंतिम स्वीकृति हेतु केंद्र सरकार (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) को भेज दिया गया है, जिसमें से 436 करोड़ 19 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

इसके अलावा बैठक में वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान हुए कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की गई। छत्तीसगढ़ में कैम्पा निधि से किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि राज्य में सिंचित व असिंचित वृक्षारोपण, क्षतिपूर्ति वनीकरण, बांस वनों की पुनर्स्थापना, वनों के घनत्व में वृद्धि के लिए सिल्वीकल्चरल कार्य, वन्यप्राणी प्रबंधन, चरागाह विकास, चेक डैम व तालाबों के माध्यम से भू-जल संरक्षण और कनेक्टिविटी सुधार के कार्य निरंतर जारी हैं। इस उच्च स्तरीय बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, पीसीसीएफ अरूण पाण्डेय, आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, वित्त सचिव डॉ. रोहित यादव, आवास एवं पर्यावरण सचिव अंकित आनंद, कैंपा सीईओ शालिनी रैना सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

छग में 5 प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों की नई पदस्थापना

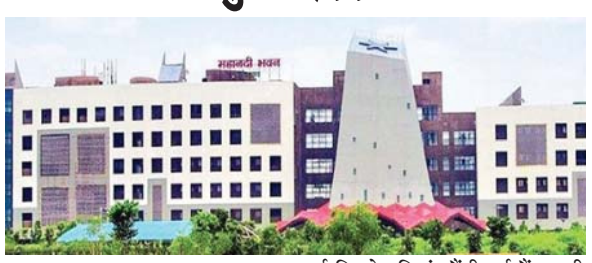

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के प्रशिक्षु अधिकारियों की नई पदस्थापना संबंधी आदेश जारी किया है।

7 अगस्त 2026 को जारी इस आधिकारिक आदेश के तहत वर्ष 2020 और 2024 बैच के कुल पांच प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA), मसूरी में फेज़-दो (Phase-II) का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद राज्य में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सभी अधिकारियों को 21 अगस्त 2026 को प्रशिक्षण से कार्यमुक्त होने के बाद अपने-अपने नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार इन अधिकारियों की नियुक्ति विभिन्न जिलों में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के पद पर की गई है। राज्य सरकार का उद्देश्य प्रशिक्षु अधिकारियों को मैदानी प्रशासन का अनुभव प्रदान करना और राजस्व एवं विकास कार्यों की जिम्मेदारी सौंपकर प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाना है।आदेश के अनुसार वर्ष 2020 बैच के आईएएस अधिकारी फड़तरे अनिकेत अशोक को भानुप्रतापपुर, जिला कांकेर में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नियुक्त किया गया है। वहीं वर्ष 2024 बैच के चार प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों को भी अलग-अलग जिलों में एसडीएम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें अरविंद कुमार टी. को बलौदाबाजार-भाटापारा, जिला बलौदाबाजार, अक्षय दोशी को डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव, क्षितिज गुरभेले को घरघोड़ा, जिला रायगढ़ तथा विपिन दुबे को कटघोरा, जिला कोरबा में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के पद पर पदस्थ किया गया है।

धोनी का कमरा सभी के लिए खुला रहता था : रहाणे

मुम्बई। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि उस समय कप्तान रहे महेन्द्र सिंह धोनी का कमरा सभी के लिए खुला रहता था।

रहाणे ने कहा कि धोनी केवल ड्रेसिंग रूम में ही नहीं बल्कि टूर के दौरान होटल के कमरे में भी एक ऐसा शांत माहौल बनाए रखते थे जो सभी को पसंद आता था। वह बेहद शांत और संयमित रहते हुए आम लोगों की तरह ही रहते थे। उनका कमरा हमेशा टीम के हर सदस्य के लिए खुला रहता था। कई बार तो पूरी टीम ही उनके कमरे में होती थी। यह एक ऐसी जगह बन गयी थी जहाँ खिलाड़ी अपनी थकान मिटाने, हंसी मजाक करने, मोबाइल या वीडियो गेम खेलने या बस आराम से समय बिताने के लिए एकत्र होते थे।

रहाणे ने इसे धोनी की ओपन डोर पॉलिसी बताया, जिसने टीम के भीतर एक सहज और स्वागत करने वाला माहौल बनाया।

इस ओपन डोर पॉलिसी के साथ एक नियम भी जुड़ा था। रहाणे ने बताया कि जब धोनी अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेते थे, तो कोई भी खिलाड़ी अंदर आने की हिम्मत नहीं करता था। हर कोई माही की निजता का सम्मान करता था, जो दिखाता है कि धोनी अपने व्यक्तित्व में संतुलन बनाए रखते थे। एक तरफ खुले दिल वाले कप्तान, वहीं दूसरी ओर अपनी निजी जगह का महत्व समझने वाले व्यक्ति। पुजारा का ये बयान पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान के उस बयान से एकदम अलग है जिसमें पठान ने आरोप लगाया था किकि जो खिलाड़ी धोनी के कमरे में जाकर उनके लिए हुक्का बनाता था, उसे ही प्लेइंग इलेवन में जगह मिलती थी। रहाणे का यह नया खुलासा जहां धोनी के एक मिलनसार और सहज कप्तान के रूप को दिखाता है, वहीं पठान का पुराना बयान एक ऐसी बहस को जन्म देता है, जो टीम चयन में व्यक्तिगत संबंधों की भूमिका पर सवाल उठाती है।

आईपीएल में एक बार हेजलवुड ने मुझे गेंदबाजी से इंकार कर दिया था : पुजारा

मुम्बई। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व टेस्ट विशेषज्ञ बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने खुलासा किया है कि आईपीएल में एक बार चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के नेट सत्र में तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने उन्हें गेंदबाजी करने से मना कर दिया था। पुजारा के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2018-19 और 2020-21 में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी सीरीज के दौरान उन्होंने हेजलवुड की गेंदों पर काफी रन बनाये थे। जिसे वह भूल नहीं पा रहे थे। ऐसे में जब वह सीएसके टीम के नेट सत्र में बल्लेबाजी करने पहुंचे तो हेजलवुड उन्हें गेंदबाजी करने के लिए तैयार नहीं हुए। पुजारा के अनुसार, हेजलवुड ने कहा, मैं उसे गेंदबाजी नहीं करूंगा। हालांकि वह मेरे टीम के साथी थे, फिर भी उन्होंने साफ इंकार कर दिया।

हेजलवुड ने कहा कि उन्होंने मजाक में ये बात इसलिए कही थी क्योंकि आईपीएल से पहले के कुछ महीनों में उन्होंने पुजारा को बहुत ज्यादा गेंदबाजी की थी, इसलिए अब वह उन्हें फिर से गेंदबाजी नहीं करना चाहते थे। पुजारा ने इसपर कहा कि हेजलवुड भले ही मजाक कर रहे थे पर असल में उन्होंने उस दिन उन्हें गेंदबाजी नहीं की थी ।

वहीं अपने अपने शुरूआती आईपीएल करियर को याद करते हुए, पुजारा ने कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के साथ बिताया समय याद किया। इस दौरान टीम के सह-मालिक और बॉलीवुड भिनेता-निमार्ता शाहरुख खान से अपनी पहली मुलाकात को भी उन्होंने याद किया। साथ ही कहा कि उनकी प्राथमिकता क्रिकेट को आगे बढ़ाने को लेकर थी। इसके अलावा उनका जोर टीम कल्चर पर भी था।

पुजारा के अनुसार, आप वहां इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि फ्रेंचाइजी ऐसा माहौल बनाती है, जहां दिग्गज खिलाड़ियों से सीखने, उनके साथ खेलने और अपने क्रिकेट को बेहतर बनाने का मौका मिलता है और यही मायने रखता है, न कि सिर्फ इसलिए कि शाहरुख मालिक हैं। यह घटनाक्रम पुजारा के उस पेशेवर रवैये को दशार्ता है, जिसमें वे हमेशा खेल और उसके सुधार को प्राथमिकता देते हैं, चाहे वह नेट्स में अपने प्रतिद्वंद्वी से जुड़े मजाक की बात हो या एक टीम में सेलिब्रिटी मालिक की मौजूदगी की।

जमशेदपुर एफसी के खिलाड़ियों ने टाटा समूह से टीम भंग करने के फैसले पर पुर्नविचार करने कहा

कोलकाता। जमशेदपुर एफसी के इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) से हटने और अपनी सीनियर टीम को भंग करने के फैसले से भारतीय फुटबॉल जगत सदमें में है।

इस घोषणा के बाद से ही क्लब के खिलाड़ी हताश हैं और उन्होंने टाटा समूह से अपने फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की है। खिलाड़ियों के अनुसार ये कदम केवल एक टीम के बंद होने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव भारतीय फुटबॉल के भविष्य के साथ ही उभरती हुई प्रतिभाओं पर पड़ेगा। भविष्य और अनगिनत युवा खिलाड़ियों के सपनों पर पड़ेगा।

गौतरतलब है कि जमशेदपुर एफसी ने इस हाल ही में कहा था कि वह 4 सितंबर से शुरू होने वाले सुपर लीग सत्र में भाग नहीं लेगी। यह घोषणा क्लब द्वारा लीग भागीदारी शुल्क जमा करने की तय समय सीमा निकल जाने के कुछ ही समय बाद की गई थी। इस फैसले के साथ ही क्लब की सीनियर टीम को भंग करने की भी घोषणा कर दी गयी जिससे खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के भविष्य पर संशय के बादल छा गये हैं।

इस फैसले से निराश क्लब के अनुभवी मिडफील्डर प्रणय हल्दर ने कह कि उन्हें टाटा समूह से ऐसी उम्मीदें नहीं थी। उन्होंने बेहद भावुक अपील करते हुए कहा, यह मेरे लिए बेहद हैरान करने वाली खबर थी। टाटा समूह से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे अपना फैसला बदलें और लीग में हिस्सा लें। हल्दर ने साथ ही कहा कि इस क्लब से उनकी कई यादें जुड़ी हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि समू के प्रमुख इस फैसले पर दोबारा विचार करेंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि आईएसएल उभरतते हुए खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा मंच है, और इसके बंद होने से कई प्रतिभाओं का भविष्य खराब हो जाएगा। वहीं पूर्व अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर अल्बिनो गोम्स ने भी क्लब को बंद करने के फैसले पर नाराजगी जतायी। उन्होंने इस मुद्दे को केवल एक क्लब का मामला मानने से इनकार करते हुए कहा कि यह भारतीय फुटबॉल के भविष्य से जुड़ा हुआ है। गोम्स ने अपनी अपील में कहा, इस क्लब को बंद करना मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं है। मैं टाटा समूह से अपील करता हूं कि वे अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। यह सिर्फ एक या दो साल की बात नहीं है, बल्कि भारतीय फुटबॉल के भविष्य का सवाल है।

इसके अलावा मिडफील्डर निखिल बारला ने भी टाटा समूह और टाटा स्टील के शीर्ष अधिकारियों से कहा कि वे युवा खिलाड़ियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने फैसले पर फिर विचार करें। उन्होंने कहा कि यह फैसला कई उभरते हुए सितारों के सपनों को तोड़ सकता है और भारतीय फुटबॉल को नुकसान पहुंचा सकता है। अब देखना है कि टाटा समूह इसको लेकर क्या कदम उठाता है।

हॉकी विश्व कप में इस बार नजर नहीं आयेगा कोई भारतीय अंपायर

नई दिल्ली। नीदरलैंड और बेल्जियम में इसी माह 15 अगस्त से शुरू रहे हॉकी विश्व कप में इस बार एक भी भारतीय अंपायर नहीं दिखेगा। तीन दशकों के बाद ऐसा पहली बार होगा जब किसी भी भारतीय अंपायर या तकनीकी अधिकारी को विश्वकप के लिए नहीं रखा गया है। इससे देश में हॉकी अंपायरिंग के भविष्य और गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं पूर्व अंतरराष्ट्रीय अंपायरों ने भी इसको लेकर चिन्ता जतायी है।। उनका मानना है कि अब हमें देश में घरेलू मुकाबलों में केवल अंपायरों की संख्या बढ़ाने की जगह पर उनकी गुणवत्ता और अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर पर भी ध्यान देना होगा। गौरतलब है कि साल साल 1998 में नीदरलैंड में हुए विश्व कप के बाद से यह पहला अवसर होगा जब टूनार्मेंट में किसी भारतीय का नाम शामिल नहीं है। वहीं यूरोपीय देशों के काफी अंपायरों को इमसें जगह मिली है। इसमें चयन के लिए प्रदर्शन में निरंतरता और अनुभव महत्वपूर्ण हैं, और यहीं पर अब भारतीय अंपायर पिछड़ रहे हैं। हॉकी इंडिया के पास भले ही अंपायरों की चार श्रेणियों में पुरुष वर्ग में 100 से अधिक और महिला वर्ग में 70 से अधिक अंपायर हैं पर एफआईएच पैनल में सक्रिय भारतीय अंपायरों की संख्या बेहद कम है। इसका कारण इस पेशे में वित्तीय सुरक्षा की कमी को बताया जा रहा है। अधिकतर अंपायरों के पास कोई स्थायी नौकरी नहीं है और उन्हें घरेलू टूनार्मेंटों से मिलने वाले वेतन पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे हालातों में कोई भी अंपायिंग में आने को उत्सुक नहीं रहेगा। एक पूर्व अंपायर ने ककहा कि केवल संख्या बढ़ाने की जगह पर अंपायरों की गुणवत्ता और उन्हें पर्याप्त अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर देने पर ध्यान देना होगा। तभी वे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय अंपायरिंग के बीच अंतर समझ सकेंगे।

दिग्गज पूर्व अंपायरों ने जतायी निराशा

लंबे प्रारुप में खेलने की तैयारी में लगे वैभव

नागपुर। उभरते हुए बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अब लाल गेंद क्रिकेट में क्रिकेट में जगह बनाने के लिए नागपुर के पास तलेगांव स्थित राजस्थान रॉयल्स (आरआर) अकादमी में अभ्यास कर रहे हैं। इस अकादमी का अपना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी है जिसमें वैभव लंबे प्रारुप के अनुसार अपने को ढ़ालने में लगे हैं। वैभव ये अभ्यास सहायक कोच विक्रम राठौर की देखरेख में कर रहे हैं। वैभव के साथ ही कई अन्य उभरते हुए क्रिकेटर भी इसमें अभ्यास कर रहे हैं।

वैभव ने अब तक सीमित ओवरों के टी20 प्रारुप में ही खेला है। 15 आईपीएल में आक्रामक बल्लेबाज के बाद उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी अवसर मिला। आईपीएल की तरह ही उन्होंने टी20 प्रारुप में भी जमकर रन बनाये। वैभव का कहना है कि उसे लंबे प्रारुप में भी खेलने में कोई परेशानी नहीं है। वैभव के अनुसार वह इस प्रारुप में भी सीमित ओवरों जितना ही सहज हैं। वर्तमान में फ्रेंचाइजी ने 10 दिन का विशेष कैंप आयोजित किया है, जिसमें वैभव के अलावा तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, शुभम दुबे, रवि सिंह और सुशांत मिश्रा जैसे उभरते खिलाड़ी अपना कौशल निखारने में लगे हैं।

इसमें से वैभव और तुषार को आगामी दलीप ट्रॉफी में ईस्ट और वेस्ट जोन से खेलना है। लंबे प्रारुप वाला दलीप ट्रॉफी, 23 अगस्त से बेंगलुरु में शुरू होगा। वहीं फ्रेंचाइजी

ने कहा है कि इस शिविर में व्यक्तिगत रूप से तैयार किए गए ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए तकनीकी कौशल विकास, शक्ति और कंडीशनिंग, कार्यभार प्रबंधन, रिकवरी और प्रदर्शन विश्लेषण जैसी चीजें शामिल हैं। इसका लक्ष्य यह पक्का करना है कि खिलाड़ी शारीरिक और तकनीकी रूप से बेहतर होकर घरेलू सत्र के लिए तैयार रहे।

यह अत्याधुनिक सुविधा विशेष रूप से पूरे साल क्रिकेटरों की सहायता के लिए बनायी गई है। इसमें मिट्टी के अलग-अलग तरह के प्रैक्टिस विकेट हैं जो घरेलू मैचों में मिलने वाली विभिन्न हालातों में खेलने के अवसर देते हैं। साथ ही लाल गेंद से खेलने की तैयारी के लिए विशेष सुविधाएं भी मौजूद हैं। इस अवसर पर कोच राठौर ने कहा, सीजन शुरू होने से पहले का समय खिलाड़ियों के लिए अपने खेल को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा अवस होता है। हर खिलाड़ी अलग-अलग कारणों के साथ आता है, चाहे वह अपने तकनीकी कौशल को निखारना हो, शारीरिक फिटनेस बनाना हो या घरेलू सीजन की चुनौतियों के लिए तैयारी करना हो। हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर हमें एक टीम के तौर पर प्रशिक्षण देते हुए हर खिलाड़ी के लिए अलग-अलग कार्यक्रम बनाने की सुविधा देता है, जिससे यह पक्का हो सके कि हर खिलाड़ी आने वाली चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार रहे।वहीं फ्रेंचाइजी के ऑपरेशन्स हेड रोमी भिंडर ने कहा, हाई परफॉर्मेंस सेंटर को दीर्घकालिक योजना के लक्ष्यों को लेकर बनाया गया है। जिससे एक विश्व-स्तरीय माहौल तैयार किया जा सके जहां हमारे खिलाड़ी पूरे साल अपने कैशल को बेहतर बना सकें।

कारोबार

यूपीआई शुल्क से दिग्गजों को मिलेगा बड़ा हिस्सा, छोटे ऐप भी होंगे प्रेरित

संभावित यूपीआई शुल्क से बाजार हिस्सेदारी में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं

नई दिल्ली। यूनीफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) भुगतान पर संभावित शुल्क का बड़ा हिस्सा फिनटेक दिग्गज फोनपे और पेटीएम के खाते में जा सकता है।

हालांकि, उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम छोटे यूपीआई ऐप को भी अपने प्लेटफॉर्म को भुनाने और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। फिनटेक क्षेत्र के कई वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि इन शुल्कों से बाजार हिस्सेदारी में तुरंत बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बजाय यह छोटे ऐप्स के लिए उपयोगकताओं को आकर्षित करने पर खर्च करने का एक वाणिज्यिक कारण प्रदान करेगा, जिससे वे अपने भुगतानों को भुना सकें।

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के आंकड़ों के अनुसार, भारत में कुल 47 थर्ड-पार्टी यूपीआई ऐप हैं। शीर्ष तीन ऐप - फोनपे, गूगल पे और पेटीएम - मात्रा के लिहाज से 83.23 फीसदी और मूल्य के लिहाज से 86.29 फीसदी की बड़ी बाजार हिस्सेदारी रखते हैं। शेष सभी ऐप मिलकर करीब 17 फीसदी हिस्सेदारी पर हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि संभावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर)

भुगतान प्रणाली में मौजूदा स्थिरता संबंधी समस्याओं को दूर करेगा। एमडीआर वह शुल्क है जो व्यापारी डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए लेनदेन मूल्य के प्रतिशत के रूप में चुकाते हैं। पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यूपीआई पर शून्य एमडीआर के कारण हर दिन 30 करोड़ मुफ्त लेनदेन होते हैं, जिसने मौजूदा परिवेश को बनाए रखने और अगले 30 करोड़ भारतीयों को डिजिटल भुगतान से जोड़ने के लिए आवश्यक धन के प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया है।

उन्होंने कहा कि यह कदम बढ़ती तैनाती, सेवा और आरबीआई अनुपालन लागतों के बीच परिवेश में स्थिरता लाएगा और सभी भागीदारों को दूरदराज के इलाकों में यूपीआई की पहुंच बढ़ाने में मदद करेगा। पिछले कुछ वर्षों में भुगतान ऐप्स ने रिवॉर्ड और कैशबैक के जरिए उपयोगकताओं को आकर्षित करने पर भारी खर्च किया है। जुपिटर मनी, नवी, कीवी, भारतपे, पॉप यूपीआई जैसे कई नए थर्ड-पार्टी यूपीआई ऐप बाजार में आए हैं, जो अक्सर भुगतान के अलावा क्रेडिट कार्ड, बिल भुगतान या ऋण जैसे विशिष्ट उपयोगों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज के अनुमान के अनुसार 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर 15-30 आधार अंकों का एमडीआर वित्त वर्ष 2027-28 तक 5,000 से 10,000 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित कर सकता है।

भारत में बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज और आई7 फेसलिफ्ट की लांचिंग होगी जल्द

नई दिल्ली। बीएमडब्ल्यू ने अपनी फ्लैगशिप सेडान बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज और इलेक्ट्रिक मॉडल बीएमडब्ल्यू आई7 के फेसलिफ्ट संस्करण की बुकिंग शुरू कर दी है। कंपनी के इस फेसलिफ्ट संस्करण की लॉन्चिंग जल्द होने वाली है। वैश्विक अनावरण के कुछ महीनों बाद अब भारतीय ग्राहक भी इन अत्याधुनिक मॉडलों को कंपनी की डीलरशिप या आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से बुक कर सकते हैं। यह नए मॉडल डिजाइन, तकनीक, इंटीरियर और पावरट्रेन के स्तर पर कई महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ आएंगे, जिससे ये पहले से अधिक प्रीमियम और हाई-टेक बन गए हैं। बाहरी डिजाइन में सबसे बड़ा बदलाव नया प्रकाशित किडनी ग्रिल है, जो रात में कार को एक विशिष्ट पहचान देता है। हेडलाइट्स को भी रीडिजाइन किया गया है, जिसमें पतली डे-टाइम रनिंग लाइट्स और मुख्य एलईडी यूनिट शामिल हैं। पीछे की तरफ पतली

टेललाइट्स और स्पोर्टी बंपर कार के लुक को पूरा करते हैं। केबिन के भीतर, डैशबोर्ड पर अब एक विशाल 17.9 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और सामने बैठे यात्री के लिए 14.6 इंच की अलग डिस्प्ले दी गई है।

यह नया बीएमडब्ल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स के साथ आता है, जो वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। रियर सीट यात्रियों के लिए 31.3 इंच की 8के थिएटर स्क्रीन भी उपलब्ध है, जो एक सिनेमाई अनुभव प्रदान करती है। सभी सीटों में इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, हीटिंग, वेंटिलेशन और मसाज जैसी लग्जरी सुविधाएं मिलती हैं। पावरट्रेन के मोर्चे पर, बीएमडब्ल्यू 740आई एक्सड्राइव में 3.0 लीटर 6 सिलेंडर पेट्रोल माइल्ड-हाइब्रिड इंजन अब 400 हॉर्सपावर और 580 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है, जबकि 740डी एक्सड्राइव डीजल 313 हॉर्सपावर और 670 न्यूटन मीटर टॉर्क पैदा करता है। इलेक्ट्रिक मॉडल बीएमडब्ल्यू आई7 में बड़ी 112.4 किलोवाट-घंटा बैटरी के साथ आई7 एम70 एक्सड्राइव वेरिएंट 680 हॉर्सपावर तक की शक्ति प्रदान करता है।

एक जनवरी, 2027 से कर्ज वसूली के नए नियम, ईएमआई नहीं भरी तो क्या बंद हो जाएगा मोबाइल ?

नई दिल्ली। अगर आपने ईएमआई पर स्मार्टफोन, लैपटॉप या टैबलेट खरीदा है और किसी वजह से किस्त भरने से चूक गए हैं, तो क्या बैंक दूर बैठकर आपका फोन लॉक कर सकता है? इस सवाल को लेकर देश भर के करोड़ों डिजिटल कर्ज लेने वालों के बीच भ्रम और डर की स्थिति बनी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन वसूली करने वाले रिकवरी एजेंटों की मनमानी को लेकर एक और सख्त फैसला सुनाया है। अगले साल से लागू होने वाले इन नए नियमों में फोन लॉकिंग और टेक्नोलॉजी आधारित बंदिशों के लिए देश का पहला रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया गया है।

क्या बैंक आपका फोन लॉक कर सकते हैं?

हां, लेकिन सिर्फ शर्तों के साथ। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि यदि आपने किसी डिवाइस (फोन, टैबलेट, लैपटॉप) को फाइनेंस कराने के लिए ही लोन लिया है और आप किस्तें नहीं चुकाते, तो बैंक उस डिवाइस को टेक्नोलॉजी के जरिये बंद सकते हैं। लेकिन वे अपनी मर्जी से कभी भी यह डिजिटल ताला नहीं लगा सकते।

फोन लॉक होने पर क्या चालू रहेगा?

आपकी इनकमिंग कॉल्स, एसएमएस सेवा या इमरजेंसी एसओएस फीचर्स बंद नहीं होंगे। बैंक या थर्ड पार्टी टेक कंपनियां आपके फोन में मौजूद पर्सनल फोटो, कॉन्टैक्ट्स, मैसेज, कॉल लॉग्स या लोकेशन हिस्ट्री को न तो देख सकती हैं और न ही एक्सेस कर सकती हैं।

रिकवरी एजेंटों की गुंडागर्दी पर लगाम

रिकवरी एजेंट केवल सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही कॉल कर सकते हैं। लोन की चर्चा केवल कर्जदार या गारंटर से होगी। पड़ोसियों, सहकर्मियों या रिश्तेदारों को फोन करना या उनके सामने सार्वजनिक रूप से अपमानित करना पूरी तरह से प्रतिबंधति होगी। शादी-ब्याह, मेडिकल इमरजेंसी या परिवार में किसी की मृत्यु के समय एजेंट घर नहीं आ सकते। बैंकों को रिकवरी वाली सभी कॉल्स रिकॉर्ड करनी होंगी और उन्हें कम से कम छह महीने तक सुरक्षित रखना होगा।

कैसे चालू होगा फोन

अगर आप बकाया राशि का भुगतान कर देते हैं, तो बैंक को एक घंटे के भीतर सभी सेवाएं फिर से चालू करनी होंगी। देरी होने पर ग्राहक को 250 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से हजार्ना देना होगा। इसकी अधिकतम राशि लोन की रकम के बराबर हो सकती है।

ई20 पेट्रोल में गड़बड़ी से तेल कंपनियों का इनकार

नई दिल्ली। देश की सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने शुक्रवार को ई20 पेट्रोल की गुणवत्ता को लेकर उठी चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि देश भर में की गई व्यापक जांच में ईंधन में नमी या क्लोराइड सम्मिश्रण का कोई प्रमाण नहीं मिला है। कंपनियों ने स्पष्ट किया कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीएमएस) यानी ई20 की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के भीतर है और उपभोक्ताओं को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तेल कंपनियों ने एक साझा बयान में कहा कि हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्टों में ई20 पेट्रोल में नमी और क्लोराइड की मात्रा को लेकर सवाल उठाए गए थे। इसके बाद पूरे आपूर्ति तंत्र (सप्लाई चेन) में अतिरिक्त और गहन परीक्षण अभियान चलाया गया। जांच के नतीजों में कहीं भी ईंधन के दूषित होने का प्रमाण नहीं मिला और सभी नमूने निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पाए गए। कंपनियों ने कहा कि ईंधन की गुणवत्ता उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। अगर किसी ऐसी समस्या की आशंका होती है जो वाहनों के प्रदर्शन या उपभोक्ताओं के भरोसे को प्रभावित कर सकती है, तो उसकी वैज्ञानिक तरीके से जांच की जाती है और आवश्यक सुधारात्मक कदम तुरंत उठाए जाते हैं।

महत्वपूर्ण ख़बर

छिंदवाड़ा को औद्योगिक हब बनाने की दिशा में तेज होंगे प्रयास : मुख्यमंत्री

- भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार औद्योगिक विकास, किसान, युवा एवं गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इन सभी वर्गों के कल्याण के कार्य मिशन मोड में सुनियोजित ढंग से संचालित किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जनविश्वास अभियान के तहत छिंदवाड़ा जिले में आयोजित उद्यमी और जनप्रतिनिधि संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि स्थानीय उद्यमियों के व्यापार और उद्योगों को प्रोत्साहन सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने स्थानीय निवेशकों से अपने उद्योगों के विस्तार की दीर्घकालिक योजना बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार औद्योगिक क्षेत्रों में पानी, निर्बाध विद्युत आपूर्ति तथा अधोसंरचना विकास सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जिले में रोजगारपरक उद्योगों, फूड पार्क, बहुफसली प्रसंस्करण इकाइयों, प्राकृतिक खेती तथा पशुपालन को बढ़ावा देने की बात कहीं।

विदिशा स्टॉप डैम मामला

हाई कोर्ट के बाद मानवाधिकार आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान; एमपी सरकार को भेजा नोटिस

विदिशा। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मध्य प्रदेश में विदिशा संसदीय क्षेत्र में बेतवा नदी पर स्थित स्टॉप डैम के खंभों से छलांग लगाकर बच्चों के स्कूल पहुंचने के मामला का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है।

हाई कोर्ट भी ले चुका है संज्ञान

उल्लेखनीय है कि इस मामले का मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भी संज्ञान ले चुका है। उसने भी निरीक्षण कराकर इस मामले में रिपोर्ट तलब की थी और अधिकारियों को तत्काल आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। हालांकि उससे पहले ही स्टॉप डैम वाला रास्ता बंद करके बच्चों के गांव वाले स्कूल को उच्चीकृत करके हाई स्कूल तक कर दिया गया था। मानवाधिकार आयोग ने कहा कि बच्चों को 15 किलोमीटर की दूरी बचाने के लिए जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ रही थी, जो बच्चों के शिक्षा और सुरक्षा के अधिकार से जुड़ा गंभीर विषय है। आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 21-ए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा कि बच्चों को सुरक्षित ढंग से स्कूल पहुंचाना भी राज्य की जिम्मेदारी है।

वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई

बता दें हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए ककरुआ और आसपास के गांवों के बच्चों को ग्राम पलोह स्थित शासकीय हाई स्कूल में इसलिए जाना पड़ता था, क्योंकि उनके गांव में उच्चीकृत विद्यालय नहीं था। चूंकि सड़क मार्ग से वहां तक जाने के लिए 15 किलोमीटर लंबा रास्ता था, इसलिए वे बेतवा नदी के स्टॉप डैम के खंभों को छलांग लगाकर स्कूल तक जाया करते थे। यहां से उनके स्कूल की दूरी महज डेढ़ किलोमीटर थी। उनके इस तरह जोखिम उठाने से मामला तब सुर्खियों में आया, जब छात्र-छात्राओं का स्टॉप डैम के खंभों पर छलांग लगाकर स्कूल जाने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर बहुप्रसारित हुआ।

वीडियो सामने आने के बाद सरकार और प्रशासन ने त्वरित कदम उठाते हुए तीन दिन के भीतर बंधेरा में हाई स्कूल शुरू कर दिया। प्रशासन अब बनाएगा स्थायी पुलः वहीं, विदिशा जिला प्रशासन ने अब बेतवा नदी पर पलोह और ककरुआ गांवों के बीच स्थायी पुल बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। लोक निर्माण विभाग (ब्रिज) पुल निर्माण का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजेगा।

तत्काल राहत के प्रयास तेज

लोक निर्माण विभाग (ब्रिज) के कार्यपालन यंत्री ए.आर. मोरे ने बताया कि तत्काल राहत के तौर पर स्टॉप डैम के खुले हिस्सों पर लोहे की जालियां बिछा दी गई हैं, ताकि बच्चों और ग्रामीणों की आवाजाही कुछ हद तक सुरक्षित हो सके।

उधर, जिला पंचायत ने इस मामले की जानकारी समय पर प्रशासन तक नहीं पहुंचाने को गंभीरता से लेते हुए जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा ग्राम पंचायत मुंडरा हरिसिंह के सरपंच और सचिव को नोटिस जारी किया है।

त्योहारों में बिना टिकट यात्रा पड़ेगी भारी

भोपाल। त्योहारों का सीजन नजदीक आते ही ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है। ऐसे में भोपाल मंडल ने बिना टिकट और अनुचित टिकट लेकर यात्रा करने वालों के खिलाफ टिकट चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। मंडल रेल प्रबंधक पंकज त्यागी के अनुसार वाणिज्य विभाग की टीम अप्रैल से जुलाई तक लगातार टिकटों की जांच कर रही है। इस दौरान 2 लाख 30 हजार 345 मामले पकड़े गए।

बिना टिकट और अनुचित टिकट पर कार्रवाई

- इनसे रेलवे को 17.50 करोड़ रुपये का राजस्व मिला। इनमें 1,05,914 बिना टिकट यात्रा, 1,23,643 अनुचित टिकट और 788 बिना बुक सामान के मामले शामिल हैं।
- पिछले साल की समान अवधि की तुलना में रेलवे की आय में 11.80 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
- वहीं, जुलाई में ही 42,139 मामले पकड़े गए और 3.75 करोड़ रुपये का राजस्व मिला। इनमें 18,533 बिना टिकट और 23,394 अनुचित टिकट के मामले थे।
- यह भी पढ़ें- इंदौर के हजारों वाहन चालकों को मिली बड़ी राहत, एयरपोर्ट से गांधी नगर मार्ग दोनों तरफ से शुरू, नहीं लगाने पड़ेंगे 4 डे के चक्कर

टिकट लेकर ही करें सफर

रेलवे की अपील है कि त्योहारों में भीड़ के बीच जल्दबाजी में बिना टिकट ट्रेन में न चढ़ें। सफर से पहले अपना टिकट जरूर बनवाएं और नियमों का पालन करें। इससे आप जुमार्ने से बचने के साथ ही परेशानी मुक्त यात्रा कर सकेंगे।

रक्षाबंधन पर बहनों की तरफ से भाइयों को डाक विभाग की किट से मिलेगा खास राखी गिफ्ट

इंदौर। रक्षाबंधन के पावन पर्व को और अधिक यादगार बनाने के लिए भारतीय डाक विभाग ने एक विशेष पहल की है। जहां मुख्य डाकघर (जीपीओ) में राखी गिफ्ट किट रखी गई है, जो बहनें अपने भाइयों को भेज सकेंगी। इन गिफ्ट 10 अगस्त से ग्राहकों को उपलब्ध करवाई जाएगी।

खास बात यह है कि विशेष बाक्स प्रसिद्ध कुकीज ब्रांड ₹कुकी बाक्स₹ के सहयोग से तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य लोगों को एक ही पैक में राखी, मिठास और शुभकामनाएं अपने प्रियजनों तक आसानी से पहुंचाने की सुविधा देना है।

इस विशेष गिफ्ट बाक्स की कीमत 121 रुपये रखी गई है। इस राशि में गिफ्ट आयटम को भेजा जा सकेगा। अलग से पोस्टल चार्ज नहीं लगेंगे। गिफ्ट बॉक्स में दो स्वादिष्ट कोकोनट कुकीज, एक पारंपरिक राखी, कुमकुम और अक्षत शामिल किए गए हैं। ताकि भाई-बहन के इस पवित्र त्योहार की सभी आवश्यक सामग्री एक ही पैकेज में उपलब्ध हो सके। आकर्षक पैकिंग के कारण यह बॉक्स उपहार के रूप में भी बेहद खास रहेगा। अधिकारियों के मुताबिक पिछले साल तक राखी और अक्षत का पैकेट रखे गए थे। मगर इस बार बाक्स में मिठाई में

कुकीज भी रखी गई है। वे कहते है कि विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभदायक होगी, जिनके परिवार के सदस्य दूसरे शहरों में रहते हैं।

विदेश भेजें राखी और पार्सल

डाक विभाग की आइटीपीएस सेवा के माध्यम से अब ग्राहक कम शुल्क में विदेशों में भी राखियां भेज सकते हैं। इसके अलावा एयर पार्सल और इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट सहित सेवाओं रखी है। इसके माध्यम से ग्राहक अपने पार्सल भी दुनिया के विभिन्न देशों में आसानी और किफायती दरों पर भेज सकते हैं। विभाग ने दो हजार से ज्यादा शहरों में पार्सल भेज सकेंगे।

हर घर तिरंगा अभियान का संदेश

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डाक विभाग इंदौर परिक्षेत्र में 10 से 13 अगस्त तक ''''हर घर तिरंगा'''' अभियान चलाएगा। इस दौरान तिरंगा साइकिल रैली और तिरंगा मार्च का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों से अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की जाएगी। इसी अभियान के तहत 11 अगस्त को इंदौर जीपीओ परिसर से एक विशाल तिरंगा मार्च भी निकाला जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिकों की भागीदारी रहेगी।

सावन में घर-घर पहुंचेगा पवित्र गंगाजल

पवित्र श्रावण मास में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए डाक विभाग गंगोत्री का पवित्र गंगाजल भी उपलब्ध करा रहा है। यह सुविधा इंदौर परिक्षेत्र के सभी प्रधान डाकघरों, चयनित उप डाकघरों और प्रमुख महादेव मंदिरों में सावन के प्रत्येक सोमवार को विशेष केनोपी के माध्यम से दी जा रही है। श्रद्धालु 250 मिलीलीटर की पैकिंग में पवित्र गंगाजल मात्र 30 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं।

इंदौर अंडरग्राउंड मेट्रो

बंगाली चौराहे से पलासिया के बीच 5 हजार मकानों के नीचे से गुजरेगी टनल, रहवासियों में डर

इंदौर : छोटा गणपति (मल्हारगंज) में मेट्रो के अंडरग्राउंड स्टेशन की खुदाई से डरे रहवासियों के बाद अब बंगाली चौराहे से पलासिया के बीच बन रहे नए अलाइनमेंट ने हड़कंप मचा दिया है। अब तक बताया जा रहा था कि अंडरग्राउंड ट्रैक कनाड़िया रोड के समानांतर गुजरेगा। हालांकि, हाल ही में वंदना नगर, गोयल नगर, साईंनाथ कॉलोनी, तिलक नगर और संविद नगर में मेट्रो द्वारा शुरू किए गए मिट्टी परीक्षण (सॉइल टेस्टिंग) से रहवासी भयभीत हैं। अंडरग्राउंड टनल कनाड़िया रोड के नीचे से न जाकर सघन कॉलोनियों और हजारों मकानों के नीचे से गुजरने की तैयारी में है। इससे चिंतित रहवासी मेट्रो के जीएम आरएस राजपूत से मिलने पहुंचे और स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। रहवासियों का तर्क है कि जब 200 फीट चौड़ी रोड उपलब्ध है, तो 2 से 3 हजार मकानों की नींव और ट्यूबवेल को खतरे में क्यों डाला जा रहा है?

ऐसा रहेगा रूट: बंगाली से पलासिया पुलिस लाइन तक टनल

मेट्रो के जीएम ने रहवासियों को अलाइनमेंट की जानकारी देते हुए बताया-

1. पहला अंडरग्राउंड स्टेशन : खजराना के बाद बंगाली चौराहे पर बनेगा।

रूट का कर्व : बंगाली चौराहे से मेट्रो कनाड़िया रोड छोड़कर लंबा टर्न लेगी। प्रभावित कॉलोनियां: में शकुंतला हॉस्पिटल, गोयल नगर से होती हुई साईंनाथ कॉलोनी, वंदना नगर, तिलक नगर, पत्रकार कॉलोनी के मकानों के नीचे से गुजरेगी।

2. दूसरा अंडरग्राउंड स्टेशनः रवींद्र नगर गायत्री मंदिर के आगे पलासिया पुलिस लाइन के समीप बनेगा। यहां से एमजी रोड जाएगी।

मेट्रो जीएम का दावा- नींव से काफी नीचे होगी टनल, पहले सर्वे करेंगे

रहवासियों के विरोध पर जीएम राजपूत ने बताया अभी अलाइनमेंट और परीक्षण का काम चल रहा है। इसके बाद जन-सर्वे किया जाएगा, जिसमें टनल के ऊपर आने वाले मकानों को चिन्हित कर उनकी वर्तमान स्थिति दर्ज होगी। जीएम के अनुसार, टनल जमीन से 50 से 60 फीट की गहराई पर बनेगी, जबकि सामान्य मकानों की नींव 10 से 15 फीट गहरी होती है।

रहवासी बोले- आंदोलन करेंगे

गोयल नगर रहवासी संघ और आसपास की कॉलोनियों के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि अलाइनमेंट में बदलाव नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। **चौड़ी सड़क का विकल्प :** 200 फीट चौड़ी संविद नगर रोड से बिना किसी तोड़-फोड़ या मकानों को खतरे में डाले आसानी से टनल बनाई जा सकती है। कानूनी व व्यावहारिक अड़चनें: कॉलोनियों के बीच से लाइन निकालने पर जमीन अधिग्रहण, मुआवजा और विस्थापन जैसी अड़चनें आएंगी। नई योजना से लगभग 5 हजार लोग प्रभावित होंगे।

इंदौर से उज्जैन का 112, महू का 46 और देवास जाने का 74 रुपये लगेगा बस का किराया

इंदौर : बसों का किराया बढ़ाए जाने के बाद परिवहन विभाग ने इंदौर से चलने वाली सामान्य बसों की नई किराया सूची शुक्रवार को जारी कर दी। इसके तहत इंदौर से महू तक का बस का किराया अब 46 रुपए लगेगा। वहीं देवास के 74, उज्जैन के 112, खरगोन के 280 तो बुरहानपुर के 400 रुपए देना होंगे। विभाग ने यह सूची बस ऑपरेटरों को दे दी है।

दरअसल, 5 साल बाद सरकार ने बसों का किराया बढ़ा दिया है। नई दरें 5 अगस्त से लागू हो गई हैं। आरटीओ प्रदीप शर्मा ने कहा सभी को शासन द्वारा निर्धारित किए गए नए किराये की सूची दे दी है। साथ ही बस ऑपरेटरों से कहा कि तय किराया ही लें, इससे ज्यादा नहीं। उन्होंने यात्रियों से भी कहा कि यदि बसों में तय किराये से ज्यादा लिया जाए तो विभाग को सूचना दें, संबंधित बस ऑपरेटर के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

ऑपरेटर बोले—संचालन काफी महंगा हो गया था

बस एसोसिएशन से जुड़े शिवसिंह गौड़, सुशील अरोरा और गोविंद शर्मा ने कहा डीजल, स्पेयर पार्ट्स, बीमा, टैक्स और संचालन लागत लगातार बढ़ती जा रही थी। ऐसे में किराया बढ़ाना जरूरी था। उन्होंने कहा किराया बढ़ने से बस ऑपरेटरों को थोड़ी राहत मिलेगी। उल्लेखनीय है कि बस का किराया बढ़ाए जाने से जहां बस संचालकों को राहत मिली है, वहीं सफर करने वाले यात्रियों की जेब पर महंगाई का असर पड़ेगा। यात्रियों के लिए सफर करना महंगा हो जाएगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव भगवान श्री महाकालेश्वर की शयन आरती में सम्मिलित हुए

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को श्रावण के पवित्र माह में श्रीमहाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर भगवान श्रीमहाकालेश्वर और श्री नंदी जी का पूजा-अर्चना की।

उन्होंने भगवान श्रीमहाकालेश्वर की शयन आरती में सम्मिलित होकर भगवान की भक्ति में झांझ बजाई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंदिर में आए श्रद्धालुओं से चर्चा कर मंदिर की दर्शन व्यवस्था के बारे में जानकारी

प्राप्त की।

श्रीमहाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष व कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह और समिति के प्रशासक श्री प्रथम कौशिक ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को भगवान श्रीमहाकालेश्वर का अंगवस्त्रम ओढ़ाकर स्मृति चिन्ह भेंट किया।

पूजा अर्चना में उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री रवि सोलंकी, उपाध्यक्ष श्री मुकेश यादव, श्री संजय अग्रवाल, संभागायुक्त श्री आशीष सिंह, नगर निगम आयुक्त श्री अभिलाष मिश्रा, सीईओ जिला पंचायत श्री श्रेयांस कूमट एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

ब्रिक्स डेलीगेट्स का भोपाल के पर्यटन स्थलों ने मोहा मन

भोपाल। मध्यप्रदेश का दिल और 'झीलों की नगरी' भोपाल इन दिनों ऐतिहासिक और गौरवशाली आयोजन का साक्षी बन रहा है। ब्रिक्स सम्मेलन न केवल देशों के बीच सांस्कृतिक सेतु का कार्य कर रहा है, बल्कि ह्यसर्वे भवन्तु सुखिनः ञ्ज हार्मनी फॉर ऑलह्ल की पावन भावना को भी जीवंत कर रहा है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिक्स देशों की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और प्राचीन परंपराओं को एक मंच पर पिरोना, कलात्मक सहयोग को बढ़ावा देना और पारंपरिक मानवीय मूल्यों को विश्व पटल पर स्थापित करना है।

भोपाल के पर्यटन स्थलों एवं अनुभव ने ब्रिक्स डेलीगेट्स का मन मोह लिया है। मध्यप्रदेश पर्यटन द्वारा अतिथियों के लिए विशेष भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। डेलीगेट्स ने हैरिटेज वॉक के माध्यम से भोपाल के

ऐतिहासिक स्थल गौहर महल, इकबाल मैदान और ऐतिहासिक मोती मस्जिद के वास्तुशिल्प का अनुभव प्राप्त हुआ। प्राकृतिक सौंदर्य से परिचित होते हुए, डेलीगेट्स ने वन विहार नेशनल पार्क की जैव-विविधता को सराहा और अपर लेक (बड़ा तालाब) में शिकारा की सैर का आनंद लिया। इसी दौरान बर्ड वाचिंग को उन्होंने अपने जीवन का एक यादगार और अद्वितीय अनुभव बताया। भ्रमण के अगले चरण में, अतिथियों ने भोपाल के जीवंत बाजारों—चौक बाजार, नया बाजार और भोपाल हाट—में हस्तकला और स्थानीय संस्कृति की अद्भुत झलक देखी। अपनी भारत यात्रा और विशेष रूप से भोपाल के हार्दिक आदर-सत्कार की प्रशंसा करते हुए डेलीगेट्स ने माना कि भोपाल न केवल अपने गौरवशाली अतीत को संजोए हुए है, बल्कि यह मेहमाननवाजी के मामले में भी विश्व के बेहतरीन केंद्रों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान एवं संगठनों के महानिदेशक, श्री हामिद मोस्तफवी ने भोपाल की अपनी यात्रा को एक 'बेहद खूबसूरत और यादगार' अनुभव बताया है। वन विहार नेशनल पार्क के भ्रमण के उपरांत उन्होंने न केवल इस स्थल की प्राकृतिक विशेषताओं और वैज्ञानिक महत्व की सराहना की, बल्कि यहाँ की ज्ञानवर्धक जानकारी को भी अत्यंत सराहा।

नीमच में बारिश के लिए गधे को खिलाए गुलाब जामुन, नगर पटेल ने की सवारी, गूंजा जल बरसा दे गोविंदा

नीमच। जिले के जावद नगर में अच्छी वर्षा और जल संकट से राहत की कामना को लेकर सदियों पुरानी परंपरा का आयोजन किया गया।

नगर के खोर दरवाजा स्थित रामलीला मैदान में विराजित प्राचीन घास भैरव का श्रद्धालुओं ने विधि-विधान के साथ पूजन किया। इसके बाद गधे को गुलाब जामुन खिलाए और नगर पटेल को गधे पर सवार कर नगर में पारंपरिक सवारी निकाली गई। इस अनोखी सवारी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मार्गों पर जुटे। सवारी में खोर दरवाजा, मोतीपुरा सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों ने भाग लिया और इंद्र देव से अच्छी वर्षा, भरपूर फसल, जल स्त्रोतों की समृद्धि तथा क्षेत्र में सुख-शांति व खुशहाली की प्रार्थना की गई। स्थानीय लोगों के अनुसार यह परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही है। मान्यता है कि घास भैरव के पूजन और इस विशेष अनुष्ठान से इंद्र देव प्रसन्न होकर क्षेत्र में अच्छी वर्षा करते हैं।

क्षेत्र में लंबे समय से अच्छी वर्षा नहीं होने से किसान, व्यापारी और आमजन सभी चिंतित हैं। खेतों में फसलें मुरझा रही है। यदि समय पर वर्षा नहीं हुई तो किसानों की आय प्रभावित होगी, जिसका सीधा असर

बाजार और आम जनजीवन पर पड़ेगा। पेयजल सहित दैनिक उपयोग के लिए भी जल संकट गहराने की आशंका बनी हुई है। इसी चिंता के बीच नगर में वर्षा की कामना को लेकर विभिन्न धार्मिक और पारंपरिक आयोजन किए जा रहे हैं। गुरुवार रात्रि को किसान परिवारों की महिलाओं ने वर्षों पुरानी लोक परंपरा पानी बंधान का आयोजन कर इंद्रदेव से अच्छी वर्षा की प्रार्थना की। महिलाएं ढोल की थाप के साथ हाथों में जल से भरी मटकियां और पूजा सामग्री लेकर अपने घरों से निकलीं। स्थानीय मान्यता है कि इस परंपरा के निर्वहन से इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और क्षेत्र में अच्छी वर्षा होती है। महिलाएं भगवान से अच्छी वर्षा, नगर की खुशहाली, किसानों की समृद्धि, परिवारों के सुख-शांति और सभी के मंगल की कामना करती हुई नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरीं। इस दौरान पूरे वातावरण में भक्ति और लोक आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। जुलूस के दौरान महिलाओं ने दुकानों और मंदिरों के सामने पारंपरिक रीति से मटकियां फोड़ीं। इस दौरान महिलाओं के मुख से लगातार राधे कृष्ण गोविंदा, जल बरसा दे गोविंदा का सामूहिक स्वर गूंजता रहा। नगरवासियों ने भी इस अनूठी परंपरा को श्रद्धा और उत्साह के साथ देखा तथा क्षेत्र में शीघ्र अच्छी वर्षा होने की कामना की।

स्वामी, प्रकाशक : अली आदिल खान द्वारा साईं प्रिंटिंग प्रेस डी 85 सेक्टर 8, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर 201301 से मुद्रित और एच 41 ए, अबुल फजल एनक्लेव, जामिया नगर, दक्षिण पूर्व दिल्ली 110025 से प्रकाशित। संपादक : अली आदिल खान
RNI No.: DELMUL/2012/47011 | Email:timesofpedia@gmail.com | समाचार चयन एवं प्रकाशन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार तथा समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे।